पीएम सूर्य घर: निशुल्क बिजली योजना ने 7.7 लाख से अधिक घरों को शून्य बिजली बिल प्रदान किया

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

लोकशक्ति

ब्राजील में कुदरत का कहर : 90 की रफ्तार से आए तूफान में भरभराकर गिरी 'स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी'

RNI Regn. No.7789/1964 | वर्ष-61 > अंक - 349 | रायपुर | बुधवार 17 दिसंबर 2025 विक्रम संवत 2082 | पृष्ठ 8 > मूल्य : 2 रू. | डाक पंजीयन : C.G./RYP DN/71/2023-25

चुनाव हारने के बाद गलत धारणाएं फैला रही कांग्रेस

एजेंसी

चुनावी सुधारों पर चर्चा के दौरान संसद के उच्च सदन को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि विपक्ष मतदाता सूचियों में घुसपैठियों का सवाल उठाते हुए मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन का विरोध नहीं कर रहा है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के कामकाज की निगरानी की जिम्मेदारी एक ही परिवार द्वारा नियंत्रित एक ही पार्टी पर है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद जेपी नड्डा ने मंगलवार को चुनावी धांधली के आरोपों को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि चुनाव हारने के बाद पार्टी गलतफ हमियां फैला रही है। चुनावी सुधारों पर चर्चा के दौरान संसद के उच्च सदन को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि विपक्ष मतदाता सूचियों में घुसपैठियों का सवाल उठाते हुए मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन का विरोध नहीं कर रहा है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के कामकाज की निगरानी की जिम्मेदारी एक ही परिवार द्वारा नियंत्रित एक ही पार्टी पर है। नड्डा ने कहा कि चुनाव परिणाम जो आए हैं, उनसे आपको (कांग्रेस को) अवश्य ही परेशानी होगी। आप कहीं और दवा लगा रहे हैं, जबकि असली समस्या कहीं और है।

जॉर्डन के क्राउन प्रिंस ने दिखाया खास सम्मान: पीएम मोदी को खुद ड्राइव करके ले गए म्यूजियम

इथियोपिया पहुंचे मोदी: गले लगाकर स्वागत

नईदिल्ली,एजेंसी

जॉर्डन की राजधानी अम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान की एक अभूतपूर्व तस्वीर सामने आई है। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय ने भारतीय प्रधानमंत्री के प्रति असाधारण आदर दिखाते हुए खुद ड्राइवर की सीट संभाल ली। युवराज खुद ड्राइवर की सीट पर बैठकर पीएम मोदी को जॉर्डन म्यूजियम तक ले गए, जिससे उनके बीच व्यक्तिगत और गर्मजोशी भरा रिश्ता साफझलकता है।

किसी राष्ट्र के प्रमुख को खुद ड्राइव करके ले जाना अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक संकेत माना जाता है। यह जेस्चर दोनों देशों के बीच गहरे, मैत्रीपूर्ण संबंधों की पुष्टि करता है। इस सम्मान को और भी महत्वपूर्ण बनाता है क्राउन प्रिंस की विरासत। युवराज अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय पैगंबर मोहम्मद की 42वीं पीढ़ी के सीधे वंशज हैं। उनके द्वारा पीएम मोदी को व्यक्तिगत रूप से यह सम्मान देना दो अलग-अलग संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच बढ़ते मेल-जोल, आपसी आदर और सद्भावना को उजागर करता है।

क्राउन प्रिंस द्वारा दिखाए गए इस व्यक्तिगत सम्मान के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जमकर वायरल हो रहे हैं। वैश्विक स्तर पर लोग इस घटना को भारत और जॉर्डन के बीच बेहतर होते राजनीतिक और व्यक्तिगत रिश्तों का प्रतीक बता रहे हैं और क्राउन प्रिंस के इस कूटनीतिक जेस्चर की व्यापक सराहना कर रहे हैं।

जॉर्डन के क्राउन प्रिंस ने खुद ड्राइवर की सीट संभाल

इथियोपिया के पीएम भी खुद ड्राइवर की सीट सम्हाली

पीएम मोदी का यह पहला इथियोपिया दौरा, पीएम से मिले गले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की चार दिवसीय यात्रा के दूसरे चरण के तहत मंगलवार को इथियोपिया पहुंचे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने अदीस अबाबा हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गले लगाकर स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को होटल तक अपनी गाड़ी से पहुंचाया। रास्ते में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को विज्ञान संग्रहालय और मैत्री पार्क भी दिखाया। गौरतलब है कि पीएम मोदी का यह पहला इथियोपिया दौरा है। बता दें कि इथियोपिया की अपनी पहली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह 'लोकतंत्र की जननी' के रूप में भारत की यात्रा और 'ग्लोबल साउथ' के लिए भारत-इथियोपिया साझेदारी क्या मायने रखती है विषय पर अपने विचार साझा करेंगे। पीएम मोदी इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा भी करेंगे। प्रधानमंत्री की इथियोपिया यात्रा से पहले विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, यह यात्रा 'ग्लोबल साउथ' में साझेदार के रूप में भारत और इथियोपिया के बीच गहरी दोस्ती और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि होगी। गौरतलब है कि मोदी इथियोपिया की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे।

आतंकवाद के खिलाफ कड़ा प्रहार, जम्मू-कश्मीर के सात जिलों में 12 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी

श्रीनगर । एजेंसी। जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर-इंटेलिजेंस विंग मंगलवार को आतंकवाद से जुड़े एक मामले और आतंकवाद के ऑनलाइन महिमामंडन करने के सिलसिले में कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर ने आतंकवाद से जुड़े एक मामले की चल रही जांच के तहत कश्मीर घाटी में कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की। यह मामला आतंकवाद की ऑनलाइन तारीफ और भर्ती गतिविधियों से जुड़ा है। ये छापेमारी पुलवामा, बडगाम, कुलगाम, श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग और कुपवाड़ा सहित सात जिलों में 12 जगहों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि ये सर्च ऑपरेशन पुलिस स्टेशन काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर में आईपीसी की धारा 153-ए और 505 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 और 18 के तहत दर्ज एफआईआर नंबर 03/2023 के सिलसिले में उचित सर्च वारंट हासिल करने के बाद किए जा रहे हैं।

पिछली सरकारों की गलतियों को सुधारने में जुटी मौजूदा दिल्ली सरकार: सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्ली एजेंसी।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जलभराव और प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों के तहत सुनहरी पुल नाले के डी-सिल्टिंग कार्यों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के सभी प्रमुख नालों की गाद निकालने का काम गंभीरता से कर रही है ताकि बरसात के समय जलभराव की समस्या से लोगों को राहत मिल सके और यमुना नदी में प्रदूषित पानी के बहाव को नियंत्रित किया जा सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद से बारापुला ड्रेन और सुनहरी पुल नाले का कई बार दौरा किया गया है। उन्होंने कहा कि जब भी बारिश होती थी, इस इलाके के आसपास की सभी कॉलोनियों में पानी भर जाता था। यह समस्या एक-दो बार नहीं, बल्कि हर मानसून में सामने आती रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस नाले की डी-सिल्टिंग का काम पहले भी कई बार किया गया है और सभी संबंधित एजेंसियां इस स्थिति से भली-भांति परिचित हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह नाला वर्ष 2010 में बनाया गया था, लेकिन इसके निस्तारण के लिए कहीं भी उचित आउटलेट नहीं दिया गया था, जिससे इसकी नियमित सफाई संभव नहीं हो पाती थी।

गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की ओर बढ़ता कदम : लोकसभा में बोले मेघवाल

नईदिल्ली,एजेंसी

- कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि कई अप्रचलित एवं पुराने कानूनों के निरसन व संशोधन का प्रस्ताव करने वाला विधेयक गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की ओर बढ़ता कदम है। मेघवाल ने निरसन और संशोधन विधेयक, 2025 को सदन में चर्चा और पारित किए जाने के लिए रखते हुए कहा कि सरकार से समाज हित में कानून बनाने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन एक समय आता है जब ऐसा लगता है कि उस कानून की उपयोगिता नहीं है या वह अपनी प्रासंगिकता खो चुका है तो ऐसे कानूनों का निरसन किया जाना चाहिए।

बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण रहा। दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण कामकाज किए गए। हालांकि, लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में वार-पलटवार का दौर साफ तौर पर देखने को मिला। मनरेगा की जगह लेने वाले विधेयक पर लोकसभा में प्रियंका गांधी बनाम शिवराज सिंह चौहान आमने सामने दिखे। वहीं, देश में अप्रचलित एवं पुराने हो चुके 71 कानूनों को निरस्त और संशोधित करने के प्रस्ताव वाले 'निरसन और संशोधन विधेयक, 2025' को लोकसभा ने मंजूरी दी। सरकार ने मंगलवार को संसद को बताया कि जलवायु परिवर्तन महिलाओं पर काम का बोझ बढ़ा रहा है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उनपर यह जोखिम ज्यादा बढ़ रहा है। - लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को सदन में कुछ सदस्यों से चुटकी लेते हुए कहा कि सदन ''ध्यान लगाने'' का स्थान नहीं है और यदि वे अपने घर से ही ''ध्यान लगाकर'' आएंगे तो उचित रहेगा। उन्होंने सदन में आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाने के बाद यह टिप्पणी की। सरकार ने विपक्ष के तीखे विरोध के बीच मंगलवार को लोकसभा में 'विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025' पेश किया, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर लाया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच 'विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)' (विकसित भारत- जी राम जी) विधेयक, 2025' पेश करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दी। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना उनका अपमान है।

सोनिया गांधी-राहुल को बड़ी राहत, नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से किया इनकार

नई दिल्ली. एजेंसी

नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए अहम कानूनी राहत माना जा रहा है. कोर्ट ने आदेश में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और उससे जुड़ी अभियोजन प्रक्रिया तब तक वैध नहीं मानी जा सकती, जब तक कि अपराध में विधिवत एफआईआर दर्ज न हो. कोर्ट ने कहा कि पीएमएएलए के प्रावधानों के तहत ईडी को जांच शुरू करने से पहले संबंधित अपराध में एफआईआर का होना अनिवार्य है।

नक्सलियों ने जमीन में गड़ा कर रखे थे आधुनिक हथियार-विस्फोटक समेत लाखों रुपए

एजेंसी। एमपी के बालाघाट में चल रहे एंटी नक्सल मूवमेंट की कार्रवाई के बीच पुलिस को नक्सलियों द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा डंप हाथ लगा है। जमीन के अंदर नक्सलियों का खजाना दबा था, जिसमें लाखों रुपये नगदी के अलावा आधुनिक हथियार, विस्फोटक भी थे नक्सलियों ने जंगल में अलग-अलग जगहों पर जमीन में आधुनिक हथियार, विस्फेटक और नगद रुपए छिपाकर रखे गए थे। इनमें सेमीऑटोमैटिक रायफल, ग्रेनेड लांचर, कारतूस, डेटोनेटर जैसे कई हथियार मिले हैं। बड़ी संख्या में अत्याधुनिक हथियार बरामद बालाघाट में पिछले दिनों आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की निशानदेही पर पुलिस को ये नक्सली डंप बरामद करने में कामियाबी मिली है। पुलिस ने सेमीऑटोमैटिक रायफ ल, ग्रेनेड लांचर, कारतूस, डेटोनेटर जैसे अन्य हथियार बरामद किये हैं। बॉक्स में छिपे रखे मिले लाखों रुपये इसके अलावा मेडिकल किट, बारूद, विस्फोटक जैसी सामग्री भी जब्त की है। साथ ही साथ जमीन में गड़ाकर करके रखे गए 11 लाख 57 हजार रुपए नगद भी जब्त किए गए हैं।

विदेश | दोनों आरोपी बाप-बेटा गए थे फिलीपींस;

ऑस्ट्रेलिया हमले पर बड़ा खुलासा: इस्लामिक स्टेट से ली आतंक की प्रेरणा

सिडनी ,एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में बॉन्डी बीच पर रविवार शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब यहूदी समुदाय के हानुका उत्सव 'चानुका बाय द सी' के दौरान अंधाधुंध गोलीबारी कर दी गई। इस सामूहिक हमले में कम से कम 15 लोगों की जान चली गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। कार्यक्रम में करीब एक हजार लोग मौजूद थे। पुलिस ने इसे आतंकी हमला करार देते हुए कहा है कि इसके पीछे इस्लामिक स्टेट (आईएस) से प्रेरित विचारधारा होने के संकेत मिले हैं।

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने मंगलवार को कहा कि शुरुआती जांच से यह स्पष्ट होता जा रहा है कि हमला आईएस की कट्टर सोच से प्रभावित था। उन्होंने इसे नफरत फैलाने वाली विचारधारा बताया, जो बीते एक दशक से लोगों को हिंसा की ओर धकेल रही है। पुलिस के अनुसार, हमलावरों की कार से घरेलू स्तर पर तैयार किए गए दो इस्लामिक स्टेट के झंडे और एक आईईडी भी बरामद हुई है।

इस हमले को अंजाम देने वाले पिता-पुत्र बताए गए हैं। 50 वर्षीय साजिद अकरम को पुलिस ने मौके पर ही मार गिराया, जबकि उसका 24 वर्षीय बेटा नवीद अकरम गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है और पुलिस हिरासत में है। जांच में सामने आया है कि साजिद के पास छह हथियारों का वैध लाइसेंस था, जिनका इस्तेमाल इस वारदात में किया गया। पुलिस कमिश्नर माल लैन्यन ने बताया कि दोनों आरोपी पिछले महीने फिलीपींस गए थे। इस यात्रा के मकसद को लेकर जांच जारी है और कुछ रिपोर्टों में सैन्य प्रशिक्षण की आशंका जताई जा रही है। नवीद अकरम 2019 में भी ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी एएसआईओ की जांच के दायरे में आ चुका था, जब उसके कथित तौर पर आईएस से जुड़े एक नेटवर्क से संपर्क की बात सामने आई थी, हालांकि उस समय उसे तत्काल खतरा नहीं माना गया था।

आतंकवाद के खिलाफ भारत-जॉर्डन का रुख एक जैसा: मोदी

एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जॉर्डन की राजधानी अम्मान में किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल-हुसैन से मुलाकात की। अल हुसैनिया पैलेस में हुई इस उच्च-स्तरीय बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय शांति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। आतंकवाद पर जॉर्डन और किंग अब्दुल्ला द्वितीय के रुख की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अम्मान और नई दिल्ली आतंकवाद के खिलाफएक जैसा, साफरुख रखते हैं। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि अम्मान में राजा अब्दुल्ला द्वितीय के साथ सार्थक चर्चा हुई। भारतङ्कजॉर्डन संबंधों को सशक्त बनाने के प्रति उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता उल्लेखनीय है। इस वर्ष हम अपने द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह महत्वपूर्ण पड़ाव हमें नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा।

इससे पहले किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें औपचारिक राजकीय सम्मान दिया गया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच रिस्ट्रिक्टेड और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठकें हुईं। इन बैठकों में दोनों नेताओं ने अपनी पिछली मुलाकातों को याद किया और भारतङ्कजॉर्डन के ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों पर चर्चा की। बैठक के दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे 140 करोड़ भारतीयों की ओर से किंग अब्दुल्ला और जॉर्डन के लोगों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। पीएम मोदी ने किंग अब्दुल्ला की मित्रता और भारत के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता की भी सराहना की।

मोदी अच्छे दोस्त और भारत अहम रणनीतिक साझेदार, अमेरिकी दूतावास ने शेयर किया ट्रंप का संदेश

एजेंसी।

भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने एक पोस्ट में कहा कि भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक का घर है। यह एक अद्भुत देश है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। प्रधानमंत्री मोदी के रूप में हमें एक महान मित्र प्राप्त हुए हैं।

भारत में अमेरिकी दूतावास ने मंगलवार को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया है और अपने ग्रेट फ्रेंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक पोस्ट में बताया कि ट्रंप ने भारत को एक 'अद्भुत देश' कहा है, जो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक का घर है। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने एक पोस्ट में कहा कि भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक का घर है। यह एक अद्भुत देश है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। प्रधानमंत्री मोदी के रूप में हमें एक महान मित्र प्राप्त हुए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की टेलीफोन पर बातचीत - ट्रंप की यह प्रशंसा प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की।

CMYK

प्रदेश का पहला बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल केंद्र बना सहारा, अब तक 800 से अधिक बुजुर्गों ने पाई राहत- नि:शुल्क जांच, उपचार और दवा से मिल रही नई उम्मीद

रायपुर। अब तक 800 से अधिक बुजुर्गों ने पाई राहत- नि:शुल्क जांच, उपचार और दवा से मिल रही नई उम्मीदअब तक 800 से अधिक बुजुर्गों ने पाई राहत- नि:शुल्क जांच, उपचार और दवा से मिल रही

नई उम्मीद बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल केंद्र (Elderly Healthcare Centers) ऐसे संस्थान हैं जो वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विशेष सुविधाएँ प्रदान करते हैं, जिनमें नियमित जाँच (ह्क्क्ष), विशेषज्ञ परामर्श (त्द्ध्द्ध्ध्ह्ल्ह्ध्ष्ध्य), दवा प्रबंधन, फिजियोथेरेपी, और घर-आधारित देखभाल सेवाएँ शामिल हैं, ताकि वे स्वतंत्र और आरामदायक जीवन जी सकें।अब तक 800 से अधिक बुजुर्गों ने पाई राहत- नि:शुल्क जांच, उपचार और दवा से मिल रही नई उम्मीद मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सरकार के दो साल में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, ग्रामीणों, महिलाओं, किसानों, युवाओं की बेहतरी के लिए अनेक योजनाएं शुरु की है, जिसका परिणाम बेहद सकारात्मक रहा। इसी कड़ी में कोरिया जिले के जिला अस्पताल परिसर बैकुंठपुर में करीब ढाई माह पूर्व शुरू किया गया प्रदेश का पहला बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल केंद्र अब वृद्धजनों के लिए सच्चा सहारा बन गया है। उम्र बढ़ने के साथ बढ़ती पीड़ा, चलने-फिरने में कठिनाई, भीड़ में अस्पताल की लाइन में लगना और छोटे-छोटे उपचारों के लिए घंटों इंतज़ार जैसी परेशानियों को देखते हुए इस विशेष केंद्र की स्थापना की गई थी। परिणामस्वरूप, आज यह केंद्र जिले के सैकड़ों बुजुर्गों को राहत देने वाला भरोसेमंद स्थान बन चुका है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में यह केंद्र खोला गया। कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने बताया कि सुशासन तभी सार्थक होता है, जब उसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से जरूरतमंदों तक पहुँचे। यह केंद्र उसी उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इस केंद्र का शुभारंभ 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर बैकुंठपुर विधायक श्री भईया लाल राजवाड़े द्वारा किया गया था। अक्टूबर से अब तक 889 बुजुर्ग यहाँ जांच और उपचार के लिए पहुँच चुके हैं, जिनमें 371 महिलाएं और 518 पुरुष शामिल हैं।यह बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल केंद्र अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, जिनमें ट्राईसाइकिल, बैलेंस बोर्ड, फुट मसाजर, पैरेलल बार, स्टेयर क्लाइंबिंग मशीन, ट्रेडमिल, मसाज चेयर, ट्रैक्शन मशीन और वेक्स बाथ जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपी और पंचकर्म जैसी उपचार सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब तक करीब 300 बुजुर्ग पंचकर्म उपचार का लाभ ले चुके हैं। केंद्र के खुलने से बुजुर्गों को अब उपचार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। शांत वातावरण, सहयोगी स्टाफ और समय पर मिल रही सेवाएं उन्हें आत्मविश्वास और राहत दे रही हैं। 77 वर्षीय श्री एस.डी. सिंह ने बताया कि वे एक माह से यहां आ रहे हैं और उपचार से काफी राहत मिली है। वातावरण भी बेहद सहयोगी है, जिससे मानसिक सुकून मिलता है। 71 वर्षीय श्री पी.एस. दावड़े ने कहा कि पैर में जलन की समस्या से परेशान थे। लगभग 10-12 दिन के उपचार से उन्हें काफी फायदा हुआ है। 76 वर्षीय श्री बी.एल. सोनी ने बताया कि कंधे के दर्द से लंबे समय से परेशान थे।

विकसित छत्तीसगढ़ का रोडमैप है छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में छत्तीसगढ अंजोर विजन 2047 पर चर्चा करते हुए कहा कि यह विजन प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का स्पष्ट रोडमैप है। उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज आने वाले वर्षों में राज्य के विकास की दिशा तय करेगा। उन्होंने इस मौके पर विकसित छत्तीसगढ के निर्माण में सहभागी बनने के लिए सभी सदस्यों से आव्हान किया। उन्होंने इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए राज्य के अतीत, वर्तमान उपलब्धियों और भविष्य की दिशा पर प्रकाश डाला।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि 14 दिसंबर 2000 को राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में छत्तीसगढ़ विधानसभा की पहली बैठक आयोजित हुई थी। यह जशपुर हॉल स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव द्वारा अपने सांसद निधि से निर्मित कराया गया था। उन्होंने इस स्मृति का उल्लेख करते हुए प्रदेश की लोकतांत्रिक यात्रा को नमन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने विज़न डॉक्यूमेंट के निर्माण के लिए वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी को बधाई देते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में यह दस्तावेज तैयार हुआ है, जो आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा तय करेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वे अब तीसरी बार देश का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके प्रयासों से भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।

महाप्रबंधक द्वारा पेंड्रारोड स्टेशन एवं पेंड्रारोडङ्कबिलासपुर रेलखंड का निरीक्षण

बिलासपुर । तरुण प्रकाश, महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा आज पेंड्रारोड स्टेशन एवं पेंड्रारोडङ्कबिलासपुर रेलखंड का निरीक्षण किया गया। उन्होंने पेंड्रारोड स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का संक्षिप्त अवलोकन कया। इस दौरान उपलब्ध यात्री सुविधाओं का भी निरीक्षण कर संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए ।इसके पश्चात महाप्रबंधक ने पेंड्रारोडङ्कबिलासपुर रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेल परिचालन, ट्रैक, सिग्नलिंग, ओएचई तथा संरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया । निरीक्षण के दौरान संरक्षा मानकों के कड़ाई से अनुपालन एवं निर्बाध रेल परिचालन सुनिश्चित करने पर विशेष बल देते हुए महाप्रबंधक ने रेल यात्रियों को संरक्षित, सुचारु एवं समयबद्ध रेल सेवाएं प्रदान करने पर जोर दिया ।स अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक, बिलासपुर श्री राजमल खोइवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा अधोसंरचना विकास एवं संरक्षा उन्नयन के माध्यम से यात्रियों को बेहतर एवं विश्वसनीय रेल सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

लोकसभा में सांसद बृजमोहन अग्रवाल की बुलंद आवाज़ : कांकेर की घटना ने फार्मास्यूटिकल वेस्ट मैनेजमेंट पर देशभर में जगाई चिंता

कांकेर में मासूम बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ पर सांसद बृजमोहन सख्त, लोकसभा में उठाया एक्सपायर दवाओं के गलत निपटान का मुद्दा

नई दिल्ली/रायपुर। जनहित के मुद्दों पर निर्भीक और संवेदनशील आवाज़ उठाने वाले सांसद बृजमोहन ने लोकसभा में कांकेर जिले के एक सब-हेल्थ सेंटर में हुई गंभीर लापरवाही की घटना को मजबूती से उठाकर पूरे देश का ध्यान फार्मास्यूटिकल वेस्ट मैनेजमेंट जैसी अत्यंत संवेदनशील समस्या की ओर आकृष्ट किया है। सांसद अग्रवाल ने सदन को अवगत कराया कि कांकेर के सब-हेल्थ सेंटर में एक्सपायर हो चुकी दवाओं को जलाए जाने से निकला जहरीला धुआं पास के स्कूल के कक्षाओं तक फैल गया, जिससे कई मासूम बच्चों को चक्कर आने और सांस लेने में तकलीफ जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। यह घटना न केवल प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण है, बल्कि पूरे राज्य और देश के लिए एक चेतावनी भी है कि गलत वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरे में डाल सकता है।लोकसभा में बोलते हुए अग्रवाल ने कहा कि देश के कई हिस्सों में एक्सपायर दवाओं को सीवेज सिस्टम, खेती की जमीन या खुले गड्ढों में फेंक दिया जाता है, जिससे जहरीले रसायन मिट्टी और भूजल को प्रदूषित कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह प्रवृत्ति भविष्य की पीढ़ियों के लिए गंभीर संकट पैदा कर रही है।सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र सरकार से छ्ष्ठस्ष्ठ की गाइडलाइंस और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के तहत पूरे देश में सख्त और स्पष्ट निर्देश जारी करने की मांग की। उन्होंने यह भी जोर दिया कि सभी संबंधित अधिकारियों और स्वास्थ्यकर्मियों को दवाओं के सुरक्षित निपटान के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाए।भविष्य में कांकेर जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए श्री अग्रवाल ने दूरदर्शी और व्यावहारिक सुझाव भी रखे, जिनमें हर जिले में एक्सपायर दवाओं के सुरक्षित डिस्पोजल के लिए विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और नए अस्पतालों को मंजूरी देने से पहले मेडिकल व फार्मास्यूटिकल वेस्ट डिस्पोजल की अनिवार्य सुविधा लागू की जाए इसके साथ ही नियमों के सख्त पालन हेतु जिला-स्तरीय कम्प्लायंस और मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाए।यह संसदीय हस्तक्षेप सांसद बृजमोहन अग्रवाल के उस दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, जिसमें वे बच्चों के स्वास्थ्य, आम नागरिकों की सुरक्षा और पर्यावरण की शुद्धता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं करते। उनकी यह पहल न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में फार्मास्यूटिकल वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर एक नई गंभीरता और जिम्मेदारी की दिशा तय करेगी।

सुकन्या समृद्धि योजना : बैंक और पोस्ट ऑफिस में खाता खोलने पर मिलेगा अधिक ब्याज

रायगढ़। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर बालिकाओं के हित और भविष्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले में सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत विभिन्न बैंकों एवं पोस्ट ऑफिसों में खाता खोले जा रहे हैं। यह योजना बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूत बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2015 से संचालित है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 वर्ष तक की बालिकाओं का खाता खोला जाता है। एक अभिभावक अधिकतम दो बालिकाओं का खाता खोल सकता है। इसके लिए बालिका का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है। यह खाता 250 रुपये की प्रारंभिक राशि से खोला जा सकता है, जबकि एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं। खाता खुलने की तारीख से 15 वर्षों तक राशि जमा की जा सकती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना पर 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर निर्धारित की गई है, जो अन्य सामान्य बचत योजनाओं की तुलना में अधिक लाभदायक है। बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर जमा राशि का आंशिक आहरण किया जा सकता है। जिले में इस वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक 2000 से अधिक बालिकाओं के खाते खोले जा चुके हैं, जिससे बालिकाओं के सुरक्षित भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लेने एवं खाता खोलने के लिए अभिभावक परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजर एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं।

नियद नेल्लानार ग्राम पंचायत चिंगेर में विकास के लिए एकजुटता का संदेश

बीजापुर। भैरमगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चिंगेर में आयोजित ग्राम सभा के दौरान ग्रामीणों ने एक अनूठी पहल करते हुए मानवसृंखला बनाकर विकास, शांति और आपसी एकता का सशक्त संदेश दिया।ग्राम सभा में बड़ी संख्या में महिला-पुरुष, युवा और बुजुर्गों ने सहभागिता की। सभी ने हाथों में हाथ डालकर मानवसृंखला बनाते हुए यह संकल्प लिया कि गांव के समग्र विकास के लिए एकजुट रहेंगे। ग्रामीणों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, बिजली, आवास, रोजगार और स्वच्छता जैसे मूलभूत मुद्दों पर मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई।इस अवसर पर ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि विकास तभी संभव है जब समाज एकजुट होकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। उन्होंने नियद नेल्लानार अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के माध्यम से शासकीय योजनाओं का लाभ

पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।ग्रामीणों ने भी अपनी समस्याएं और सुझाव खुलकर रखे। ग्राम सभा में पारदर्शिता, सहभागिता और आपसी विश्वास का माहौल देखने को मिला। मानवसृंखला के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि हिंसा नहीं, विकास ही समाधान है और गांव का भविष्य शिक्षा, रोजगार और सामूहिक प्रयासों से ही उज्ज्वल बनेगा।कार्यक्रम के अंत में सभी ग्रामीणों ने शांति, सद्भाव और विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। ग्राम पंचायत चिंगेर में आयोजित यह ग्राम सभा और मानवसृंखला क्षेत्र में एकता और विकास का प्रतीक बनकर उभरी है जो अन्य ग्राम पंचायतों के लिए भी प्रेरणास्रोत सिद्ध होगी।

कोण्डागांव जिला ने बस्तर ओलंपिक में जीते 51 पदक, कृतिका और सुशीला बने यूथ आईकन

कोण्डागांव। जगदलपुर में 11 दिसंबर से शुरू संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक का समापन 13 दिसंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में हुआ। जिसमें संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के विजेताओं को मुख्य अतिथि के हाथों सम्मान मिला, जिसमें जिले की कृतिका मरकाम और सुशीला नेताम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर कोण्डागांव जिले का मान बढ़ाया और यूथ आईकन घोषित किए गए। वरिष्ठ खेल अधिकारी ने बताया कि संभाग स्तरीय आयोजन में कोण्डागांव जिले के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल 51 पदक हासिल किया है, जिसमें 16 स्वर्ण, 14 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। सुशीला ने आर्चरी में

तो कृतिका ने एथलेटिक्स दिखाया दमजिला स्तरीय बस्तर ओलंपिक में प्रथम स्थान प्राप्त कर संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सुशीला नेताम ने बताया कि उन्होंने आर्चरी में 50 और 30 मीटर की प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया, वहीं नेशनल गेम्स में तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार ग्राम पीढ़ापाल माकड़ी विकासखण्ड की रहने वाली कृतिका मरकाम ने बताया था कि पिछले तीन वर्ष से खेलती आ रही हैं। बस्तर ओलंपिक के एथलेटिक्स जूनियर वर्ग में 100 मी., 200 मी. और 4×100 रिले प्रतियोगिता में छह जिलों के खिलाड़ियों से मुकाबला रहा, जिसमें तीनों श्रेणी में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

अवैध कोल लेवी वसूली मामले में आरोपी जयचंद कोशले के विरुद्ध लगभग एक हजार पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित अवैध कोल लेवी वसूली प्रकरण में आर्थिक सीबीआई ने आरोपी जयचंद कोशले के विरुद्ध लगभग एक हजार पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। यह अभियोग पत्र अपराध क्रमांक 03/2024 के तहत आज दिनांक 15 दिसंबर 2025 को विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रायपुर में प्रस्तुत किया गया। वर्तमान में आरोपी जयचंद कोशले केंद्रीय जेल रायपुर में निरुद्ध है।

ईओडब्ल्यू द्वारा दाखिल अभियोग पत्र में जयचंद कोशले के खिलाफभारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420, 384, 467, 468, 471 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 7, 7ए एवं 12 के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, अभियुक्त जयचंद कोशले उर्फ जय, तत्कालीन मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ रहते हुए सौम्या चैरसिया का निज सहायक था और उसके अधीनस्थ के रूप में कार्य कर रहा था। वह अवैध कोल लेवी वसूली से प्राप्त भारी नगद राशि का वास्तविक रिसीवर और मध्यस्थ था। जप्त की गई डायरी में जय नाम से अंकित सभी प्रविष्टियां जयचंद कोशले और सौम्या चैरसिया से संबंधित पाई गई हैं, जो अवैध लेन-देन की पुष्टि करती हैं। ईओडब्ल्यू के अनुसार, जयचंद कोशले अपराध की पूरी श्रृंखला में एक अहम कड़ी रहा। वह न केवल अवैध रूप से वसूली गई रकम को भौतिक रूप से प्राप्त करता था, बल्कि उसे सौम्या चैरसिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी निभाता था। इस प्रकार अवैध धन की रिसीविंग, कस्टडी और ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया में उसकी सक्रिय भूमिका रही। जांच में सामने आया है कि जयचंद कोशले, सौम्या चैरसिया के निर्देश पर सूर्यकांत तिवारी के निवास सहित अन्य स्थानों से रकम प्राप्त करता था और फिर यह राशि मनीष उपाध्याय या सौम्या चैरसिया द्वारा बताए गए व्यक्तियों को सौंपता था। ईओडब्ल्यू के अनुसार, अभियुक्त ने अवैध कोल लेवी वसूली से लगभग 7 से 8 करोड़ रुपये सौम्या चैरसिया के लिए प्राप्त किए। जांच के दौरान सूर्यकांत तिवारी और अन्य आरोपियों के मोबाइल फोन से जप्त डिजिटल साक्ष्यों में लेवी से प्राप्त रकम का पूरा लेखा-जोखा मिला है। इसके साथ ही रियल टाइम एंट्री के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में जय नाम से संबंधित कई प्रविष्टियां भी पाई गई हैं, जो अभियुक्त की संलिप्तता को मजबूत रूप से प्रमाणित करती हैं। इसके अतिरिक्त, अनिल टुटेजा और सौम्या चैरसिया के बीच हुई चैट्स भी सामने आई हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि जयचंद कोशले, सौम्या चौरसिया के निर्देश पर गोपनीय कार्यों और महत्वपूर्ण फाइलों व दस्तावेजों को अनिल टुटेजा तक पहुंचाने का काम भी करता था।

मनरेगा में डिजिटल क्रांति की दिशा में बड़ा कदम, युक्तधारा पोर्टल से होगी पारदर्शी योजना

पारदर्शिता और जवाबदेही को नई मजबूती मिलेगी, जिससे ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

बीजापुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को अधिक पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी बनाने की दिशा में भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की है। इसके तहत ग्राम पंचायतों में होने वाले सभी योजनांतर्गत कार्य अब जीआईएस आधारित युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से योजना बनाकर क्रियान्वित किए जाएंगे।वित्तीय वर्ष 2026-27 से मनरेगा के सभी कार्यों को युक्तधारा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी क्रम में बीजापुर जिले की 96 ग्राम पंचायतों में युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से जीआईएस आधारित प्लान तैयार कर अपलोड कर लिया गया है, जो जिले के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से अब ग्राम सभा द्वारा तय प्राथमिकता क्रम के अनुसार ही कार्यों की स्वीकृति दी जाएगी। जिले में प्राकृतिक संसाधन संवर्धन, जल संरक्षण एवं कृषि से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी गई है, जिससे ग्रामीण आजीविका को मजबूती मिलेगी।युक्तधारा पोर्टल की प्रमुख विशेषताएँ एवं लाभयुक्तधारा पोर्टल पर जीआईएस एवं सैटेलाइट मैपिंग के माध्यम से क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का सटीक विश्लेषण किया जा सकेगा। इससे जल संरक्षण, भूमि विकास, वनीकरण जैसे कार्यों की वैज्ञानिक और प्रभावी योजना बनाना संभव होगा।इस पहल से टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण, ग्राम पंचायत स्तर पर डाटा आधारित निर्णय, योजनाओं में दोहराव की रोकथाम तथा कार्यों की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जा सकेगा।युक्तधारा पोर्टल के सफल क्रियान्वयन से मनरेगा में डिजिटल पारदर्शिता और जवाबदेही को नई मजबूती मिलेगी, जिससे ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना : सपनों को मिली नई उड़ान

आर्थिक सहयोग से भूषण साहू की उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ

रायपुर । छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माणी श्रमिक श्रीमती चंदा बाई साहू, पति श्री हरिशंकर साहू, निवासी ग्राम सिंधौरीकला, विकासखंड कुरूद, जिला धमतरी के परिवार के लिए मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना आशा की किरण बनकर आई है।

श्रीमती चंदा बाई साहू एक निर्माणी श्रमिक (रेजा) के रूप में कार्य करती हैं तथा उनके पति भी दैनिक मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। सीमित आय के कारण उच्च शिक्षा का सपना अधूरा प्रतीत हो रहा था। इसी बीच श्रम विभाग से संपर्क के दौरान उन्हें निर्माणी श्रमिकों के बच्चों हेतु संचालित

मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना की जानकारी मिली।

योजना के अंतर्गत उनके पुत्र श्री भूषण साहू, जो कि ष्ठद्बश्चद्यश्र कॉलेज, रायपुर में डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी (द्वितीय वर्ष) में अध्ययनरत हैं, के लिए आवेदन किया गया। सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाईन आवेदन करने के कुछ ही दिवसों में राशि रूपये 82,496/ सीधे डी.बी.टी. के माध्यम से हितग्राही के खाते में प्रदान की गई। इस आर्थिक सहयोग से भूषण साहू की उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ।

हितग्राही श्रीमती चंदा बाई साहू ने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण बच्चों को पढ़ाने का सपना अधूरा लग रहा था, परंतु योजना से मिली सहायता ने उनके परिवार को संबल दिया। वहीं, पिता श्री हरिशंकर साहू ने कहा कि वे चाहते थे कि उनका बेटा मजदूरी के बजाय शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़े और आत्मनिर्भर बने। योजना से मिली सहायता से उनका यह सपना साकार हो रहा है।

श्रम पदाधिकारी श्री नंदकिशोर साहू ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत निर्माणी श्रमिकों के मेधावी बच्चों-सामान्य एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरतकृको पात्रता अनुसार सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 467 तथा 2025-26 में 505 बच्चों को लाभ दिया जा चुका है। आगामी वर्षों में सभी पात्र बच्चों को लाभांवित करने का लक्ष्य निर्धारित है। इच्छुक हितग्राही ÷श्रमेव जयते÷ ऐप अथवा जिला एवं जनपद पंचायतों में स्थापित श्रम संसाधन केंद्रों से निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं।

श्री हरिशंकर साहू ने मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम मंत्री, जिला प्रशासन तथा श्रम विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना श्रमिक परिवारों के बच्चों को शिक्षा के माध्यम से उज्ज्वल भविष्य प्रदान कर रही है।यह कहानी प्रमाण है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं जब ज़मीन तक पहुंचती हैं, तो श्रमिक परिवारों के सपनों को नई दिशा और उड़ान मिलती है।

भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का राजनीतिक सफर

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत बतौर कार्यकर्ता हुई। वे 2006 में पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। वे लगातार पाँच बार विधायक निर्वाचित हुए। श्री नबीन 2008 में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य रहे, साथ ही युवा मोर्चा के सह प्रभारी भी बने। 2010 से 2013 में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री बने। 2016 से 2019 तक उन्होंने बिहार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दायित्व निर्वहन किया। 2019 में सिक्किम में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की ओर से उन्हें चुनाव प्रभारी का दायित्व दिया गया। इसके साथ ही सिक्किम में भाजपा संगठन प्रभारी के रूप में भी वे अपने दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। 2021 से 2024 में छत्तीसगढ़ राज्य में सह प्रभारी के रूप में संगठन ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी, जिसका उन्होंने बखूबी निर्वहन किया और 2024 में छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा चुनाव प्रभारी बनाए गए और उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में 10 लोकसभा क्षेत्र में जीत भाजपा को मिली। 2024 में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रभारी के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। वर्तमान में श्री नबीन बिहार सरकार में पथ निर्माण विभाग तथा नगर विकास एवं आवास मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही अब उन्हें भाजपा राष्ट्रीय संगठन ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में भी में उत्साह का माहौल है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने SIR की प्रगति की समीक्षा की

बीएलओ ऐप से गणना पत्रक अपलोड अनिवार्य :- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

रायपुर, 15 दिसंबर (आरएनएस)। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार की अध्यक्षता में विशेष गहन पुनरीक्षण (स्ढ्ढक्र) की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदाता सूची के अद्यतन कार्य की विस्तार से समीक्षा की गई।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने सभी रजिस्ट्रीकरण निर्वाचन अधिकारियों (श्वक्रह्) एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण निर्वाचन अधिकारियों (ष्श्वक्रह्) को निर्देशित किया कि अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में गणना पत्रकों का भौतिक परीक्षण कर बीएलओ ऐप के माध्यम से अनिवार्य रूप से अपलोड कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं, उनके संबंध में आवश्यक प्रमाण सुरक्षित रखा जाए। कुमार ने निर्देश दिए कि छूटे हुए सभी पात्र मतदाताओं का पुनरीक्षण सुनिश्चित किया जाए तथा॒स्ष्ठ (अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत) श्रेणी के मतदाताओं का भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप सटीक सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही ठ्ठष्श्चद्यद्वह्लद्गस्त्र (अप्राप्त) गणना पत्रकों की सूची के संबंध में राजनीतिक दलों के बीएलए के साथ अनिवार्य रूप से समन्वय बनाकर कर उनके हस्ताक्षर प्राप्त करने के निर्देश भी दिए गए।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को मतदाता सूची के अद्यतन कार्य को अत्यंत संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे।बैठक में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, नगर निगम आयुक्त विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन, उप मुख्यनिर्वाचन पदाधिकारी श्री जय उराव और मनोज कोसरिया, डिप्टी डीईओ नवीन कुमार ठाकुर सहित समस्त ईआरओ एवं एईआरओ सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को मतदाता सूची के अद्यतन कार्य को अत्यंत संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा।

माननीय मंत्री श्री ओ पी चौधरी की प्रेस वार्ता : आवास एवं पर्यावरण विभाग

रायपुर। प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ संवाद ऑडिटोरियम में प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में आवास एवं पर्यावरण विभाग ने विगत दो वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। लोगों को किफायती आवास की उपलब्धता, बेहतर रहवासी सुविधा, आजीविका के साधनों के विकास के साथ ही पर्यावरण अनुकूल ईज आफ लिविंग का ध्यान रखते हुए इन दो सालों में काम किया गया है। विभाग द्वारा किये गये दो सालों से नागरिक जीवन बेहतर हुआ है और राज्य की उज्ज्वल भविष्य की ठोस नींव रख दी गई है।

मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि दो साल पहले छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा था। 3200 से अधिक आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों का विक्रय नहीं हो सका था। 735 करोड रूपए का बकाया था। मंडल को ऋण मुक्त करने के लिए यह राशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई। वर्तमान में मंडल पर कोई ऋण नहीं है। जिन संपत्तियों का विक्रय लंबे समय से नहीं हुआ था, उनके विक्रय के लिए सरकार द्वारा एकमुश्त निपटान योजना ओटीएस-2 आरंभ की गई। इसके माध्यम से इन संपत्तियों पर 30 प्रतिशत तक की छूट उपलब्ध करायी गई। इस योजना को सफलता मिली और 9 महीनों में ही 1251 संपत्तियों का विक्रय हुआ और इस योजना के माध्यम से 190 करोड रुपए का राजस्व अर्जित किया गया। यह राशि आगामी परियोजनाओं में व्यय की जाएगी, ताकि अधिकतम हितग्राहियों को किफायती आवास एवं व्यावसायिक संपत्ति का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि भविष्य में अविक्रित स्टॉक से बचने के लिए नई निर्माण नीति लागू की गई है। अब मांग आधारित निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। बाजार की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार परियोजनाएं शुरू होंगी। इससे वित्तीय जोखिम कम होगा। नई नीति के अनुसार 60 प्रतिशत या प्रथम 3 माह में 30 प्रतिशत पंजीयन अनिवार्य किया गया है। इसके पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। यह व्यवस्था परियोजनाओं की व्यवहार्यता सुनिश्चित करेगी। नागरिकों की मांग को प्रत्यक्ष रूप से महत्व मिलेगा।श्री चौधरी ने कहा कि आवंटियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल को और सुदृढ किया गया है। प्रक्रियाएं सरल और समयबद्ध हुई हैं। नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एआई आधारित चैटबॉट के माध्यम से 24म7 जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता कम हुई है। पारदर्शिता और सुविधा दोनों में वृद्धि हुई है।मंत्री श्री चौधरी ने रायपुर विकास प्राधिकरण की उपलब्धियों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 193 करोड रूपए की लागत से प्राधिकरण द्वारा पीएम यूनिटी मॉल का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही टिकरापारा में 168 फ्लैट का निर्माण प्रस्तावित है। जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गई है। जनवरी से प्राधिकरण द्वारा ऑनलाईन प्रणाली की शुरूआत की गई है।

ऑस्ट्रेलिया-भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद की 3वी बैठक में एनआईटी रायपुर को एसपीएआरसी परियोजना के लिए मान्यता

रायपुर । राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की प्रमुख पहल एसपीएआरसी के अंतर्गत एक प्रतिष्ठित संयुक्त शोध परियोजना प्राप्त होने पर औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान की गई है। यह घोषणा 8 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित ऑस्ट्रेलियाङ्कभारत शिक्षा एवं कौशल परिषद एआईईएससी की तीसरी बैठक के दौरान की गई। इस परियोजना को माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान एवं ऑस्ट्रेलिया के माननीय शिक्षा मंत्री श्री जेसन क्लेयर द्वारा संयुक्त रूप से स्वीकृत किया गया, जो दोनों देशों के बीच शिक्षा एवं शोध सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड का शानदार आयोजन : मैनपाट के करमा रिसॉर्ट में 19 दिसंबर को धूमधाम से लोकनृत्य प्रतियोगिता

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला

रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड राज्य की स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 8 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025 तक विशेष गतिविधियों और प्रतियोगिताओं की भव्य श्रृंखला आयोजित कर रहा है। प्रदेश के विभिन्न पर्यटन केंद्रों, रिसॉर्ट्स और पर्यटन बोर्ड के प्रधान कार्यालय रायपुर में रचनात्मक कार्यक्रमों का दौर चल रहा है। इनका मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है।

इसी कड़ी में पर्यटन बोर्ड 19 दिसंबर 2025 को सरगुजा जिले के मैनपाट स्थित करमा रिसॉर्ट में लोकनृत्य प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है। प्रतियोगिता में

प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 7 हजार रुपये नगद, द्वितीय को 5 हजार रुपये तथा तृतीय को 3 हजार रुपये नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सभी विजेताओं को प्रमाणपत्र भी भेंट किए जाएंगे।

प्रचार सामग्री में स्थान और व्यापक पहचान का अवसरप्रतियोगिता के दौरान कैद किए गए छायाचित्रों और वीडियो को छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड की प्रचार सामग्री तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रमुखता से स्थान दिया जाएगा। इससे प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। ये आयोजन न केवल स्थानीय पर्यटन को गति देंगे, बल्कि युवाओं में लोककला के प्रति उत्साह भी जगाएंगे। पर्यटन बोर्ड ने राज्य के युवाओं, पर्यटकों और आम नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है।

धमतरी को मिली विकास की बड़ी सौगात, फोरलेन सड़क सहित कई सड़क निर्माण कार्यों को अनुपूरक बजट में शामिल

धमतरी । विधानसभा सत्र के दौरान जिला धमतरी को विकास की दिशा में एक बड़ी और महत्वपूर्ण सौगात मिली है। सिहावा चौक से कोलियारी तक लगभग 5 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क के निर्माण हेतु 6900 लाख रुपये की अनुमानित राशि को अनुपूरक बजट में शामिल किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस बहुप्रतीक्षित निर्माण कार्य के साथ ही जिले की अन्य महत्वपूर्ण सड़क निर्माण योजनाओं को भी बजट में शामिल किया गया है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं धमतरी की पूर्व विधायक रंजना साहू ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, लोक निर्माण मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री माननीय अरुण साव जी तथा वित्तमंत्री माननीय ओपी चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया है। रंजना साहू ने कहा कि सिहावा चौक से कोलियारी तक का मार्ग अत्यंत व्यस्त मार्ग है, जहां से प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं, फोरलेन सड़क के निर्माण से यातायात का दबाव कम होगा, दुर्घटनाओं में कमी आएगी और आवागमन अधिक सुरक्षित एवं सुगम बनेगा, साथ ही यह सड़क व्यापार, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी नई मजबूती प्रदान करेगी।

प्रदेश में शीघ्र ही दूर संचार के 5 हजार नए टॉवर लगाए जाएंगे : मुख्यमंत्री साय

513 टॉवरों की स्वीकृति दी दूर संचार विभाग ने

रायपुर, 15 दिसंबर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश में 5 हजार दूर संचार के नए टॉवर लगाए जाएंगे, जिसमें भारत सरकार के दूर संचार विभाग ने 513 की अनुमति प्रदान कर दी है।

विधानसभा में आज भाजपा की श्रीमती रेणुका सिंह ने अपने भरतपुर सोनहत विधाानसभा क्षेत्र में बताया कि कई गांवों में दूर संचार टॉवर नहीं होने के कारण सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि कोरिया के 25, भरतपुर-सोनहत के 93 गांवों में टॉवर की स्वीकृति नहीं मिली है, जिसके कारण गांव वालों को काफी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि दूर संचार विभाग और कलेक्टर द्वारा जानकारी अलग-अलग दी जाती है, जिससे परेशानी हो रही है। विधायक श्रीमती रेणुका सिंह ने कहा कि भारत सरकार ने बैगा जनजाति को संरक्षित जाति घोषित किया है, इसलिए यहां पर मोबाइल टॉवरों की विशेष सुविधा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सोनपुर से कोई घायल होता है तो उसे बैकुण्ठपुर आना पड़ता है, जिससे बहुत परेशानी होती है। रेणुका सिंह ने कहा कि धान खरीदी को लेकर भी बहुत परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही भारत के दूर संचार विभाग को टॉवर लगाने के लिए पत्र लिखा जाएगा, इसकी अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरिया जिले के 290 गांवों में नेटवर्क मिल रहा है। सोनहत क्षेत्र दो जिले में आता है कोरिया और मनेन्द्रगढ़। उन्होनें कहा कि शीघ्र ही नेटवर्क उपलब्ध करा देंगे।

विधानसभा में आज सेनटरी नैपकिन की खराबी को लेकर सत्तारूढ़ दल के विधायक धरमलाल कौशिक ने महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी

राजवाड़े को घेरा उन्होंने ने कहा कि उनका जवाब संतोष पूर्वक नहीं है। उन्होंने परिशिष्ट में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि आज विधानसभा का प्रश्नकाल का पहला दिन है इसलिए आप प्रश्न पूछे। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि सेनटरी नैपकिन मशीन की जांच विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाती है, इसकी जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने बताया कि कितनी मशीन बंद और कितनी चालू है इसका आंकड़ा सदन में दिया है।

बेरोजगारी भत्ता, विपक्ष ने किया सदन से वाक्आउट

विधानसभा में आज बेरोजगारी भत्ता को लेकर कांग्रेस के लखेश्वर बघेल ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर है। इस मुद्दों को लेकर भूपेश बघेल, उमेश पटेल और अजय चन्द्राकर बीच तीखी नोकझोक हुई। विधानसभा में आज कांग्रेस के लखेश्वर बघेल ने प्रदेश में पूर्व पंजीकृत बेरोजगारों और बेरोजगारी भत्ता को लेकर कौशल विकास मंत्री गुरू खुशवंत साहेब से प्रश्न पूछा। गुरू खुशवंत साहेब ने बताया कि प्रदेश में कुल 11 लाख पंजीकृत बेरोगार हैं। जिनकी संख्या 15 लाख 47 हजार हो गई है। अजय चन्द्राकर ने कहा कि उमेश पटेल जब मंत्री थे, तब उन्होंने सदन को गलत जानकारी तथा गुमराह किया। उन्होंने कहा कि सदन में उन्होंने जो कहा था मेरे पास उसका रिकॉर्ड है। भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रही है। उमेश पटेल और श्रीमती संगीता सिन्हा ने आरोप लगाया कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। कौशल विकास मंत्री गुरू खुशवंत साहेब के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। विपक्ष ने नारा लगाया बेरोजगारी भत्ता देना होगा। घड़ियाली आंसू बहाना बंद करों बजट में प्रावधान है तो भत्ता दो। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस के लखेश्वर बघेल के मूल प्रश्न में भत्ता देने का प्रश्न नहीं पूछा गया है, इस पर कांग्रेस के सदस्यों ने आपत्ति की। विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से वाक्आउट कर चले गए। भाजपा के अजय चन्द्राकर आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा झारखंड राज्य से इस अभियान का शुभारंभ किया गया है, इसके लिए 707 करोड़ रूपए प्राप्त हुए हैं।

कलेक्टर ने रायपुर साहित्य उत्सव को लेकर निजी स्कूलों के प्राचार्य एवं साहित्यकारों की ली बैठक

रायपुर । रायपुर साहित्य उत्सव के आयोजन की तैयारियों को लेकर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने निजी विद्यालयों के प्राचार्य एवं साहित्यकारों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने साहित्य उत्सव के स्वरूप, प्रस्तावित गतिविधियों तथा आयोजन को प्रभावी एवं सफल बनाने आग्रह किया और सभी से सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया। कलेक्टर डॉ. सिंह ने बताया कि रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तर्ज पर किया जाएगा, जिसमें बच्चों, युवाओं एवं शिक्षकों की विशेष भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में साहित्य के प्रति रुचि विकसित होती है और भविष्य के अच्छे लेखक एवं साहित्यकार तैयार होते हैं। बैठक में ओपन माइक जैसी गतिविधियों के आयोजन के निर्देश भी दिए गए, जिसके अंतर्गत बच्चों द्वारा लिखी गई रचनाओं का मंच से प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही बच्चों द्वारा रचित कृतियों का संकलन, छत्तीसगढ़ी गीतों का संग्रह, क्विज प्रतियोगिताएं तथा शिक्षकों द्वारा किए गए लेखन कार्यों का संकलन भी साहित्य उत्सव का हिस्सा होंगे। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यह साहित्य उत्सव केवल मंचीय कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि साहित्य में रुचि रखने वाले सभी लोगों की श्रोता के रूप में भी व्यापक सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रम को और अधिक प्रेरक बनाने के लिए बच्चों हेतु विभिन्न साहित्यिक प्रतियोगिताओं के आयोजन पर विशेष जोर दिया गया, जिससे वास्तविक साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मंच मिल सके। उन्होंने निजी स्कूलों के प्राचार्यों एवं साहित्यकारों से अपील की कि वे विद्यालय स्तर पर नियमित साहित्यिक गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन करें, ताकि बच्चों में रचनात्मकता विकसित हो और जिले में साहित्यिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिल सके और जिले में साहित्यकारों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो सके।

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

संपादकीय

बेबुनियादी आरोप ना लगाएं राहुल

चूंकि राहुल गांधी ने बीजेपी पर चुनाव आयोग की मदद से चुनाव जीतने का इल्जाम लगाया, तो निशिकांत दुबे ने ये भी गिना दिया कि आजादी के बाद 64 साल के राज में कांग्रेस ने किस किसको चुनाव आयुक्त बनाया और उनसे फायदा लेने के बाद उन्हें इनाम में क्या दिया। बहस के पहले दिन विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने EVM पर सवाल उठाए, स्ढुक्को रोकने की मांग की। राहुल गांधी ने मांग की कि विपक्षी दलों को EVM का access दिया जाए, विपक्ष को ये जानने का हक है कि EVM में कौन सा सॉफ्टवेयर है, EVM कैसे काम करती है। राहुल ने कहा कि विपक्षी दलों को machine readable वोटर लिस्ट दी जाए, चुनाव आयुक्तों को immunity देने वाला क़ानून वापस हो, तभी चुनावों पर लोगों कै भरोसा कायम होगा।

समय आगे बढ़ गया मेरे आगे।

चिड़ियाँ बची रहें
अपने खुले आकाश में।

पृथ्वी बची रहे
बस इतना ही नहीं,
बल्कि ऐसे बचे
कि उसकी साँसों में
मिट्टी की महक हो।

बची रहे आग
जो उजाले दे,
न कि घर जलाए।
बची रहे नदिया
जो प्यास बुझाए,
न कि शव ढोए।

चिड़ियाँ बची रहें
अपने खुले आकाश में,
झरने बचें

पत्थरों के हृदय से फूटते
निर्मल गीत की तरह।

पहाड़ बचें–
झुके नहीं, टूटे नहीं,
हरे-हरे पेड़ बचें
जिनकी छाया में
थकान उतरती है।

रोटी बचे
पसीने की इज़्ज़त के
साथ,
चावल, मक्का, बाजरा बचें
भूख से पहले।
समंदर बचे–
नीला, गहरा,
लालच से अछूता।

पुस्तकें बची रहें

ताकि विचार
अंधे न हो जाएँ।
मनुष्य बचे–
केवल साँस लेने के लिए
नहीं,
मनुष्य के लिए।

मनुष्य ऐसा बचे
कि मनुष्य
मनुष्य का शत्रु न बने।
स्त्री की कोख बचे–
डर से नहीं,
सम्मान से भरी हुई।

नन्हीं बच्चियाँ बची रहें
हँसी के पूरे अधिकार के
साथ,
ताकि आने वाली पीढ़ियाँ
सिर्फजन्म न लें,

बल्कि सुरक्षित जी सकें।

पृथ्वी बचे
मनुष्य के लिए,
और मनुष्य बचे
पृथ्वी के लिए।

बची रहे मानवता–
नन्हीं बच्चियों के लिए,
चिड़ियों के लिए,
फूल, पत्तियों और
कोमल कलियों के लिए।

क्योंकि
अगर यह सब नहीं बचा,
तो बचा रहना
सिर्फएक आदत बन
जाएगा।

– संजीव ठाकुर

QR CODE SCAN
कर प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़िये ऑनलाईन

PM : 2024 - Vishwa Sarkar Ka Vikalp
Modimaya_ Vaidik_Netritva
Rashtriya Ekta
DLF-Vadra-Bhrasht Tantra
Silent Assassins Jan11,1966
Accursed & Jihadi Neighbour

इच्छा मृत्यु : संवेदना एवं संविधान के बीच फंसा मानवीय प्रश्न

ललित गर्ग
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

इच्छा मृत्यु यानी व्यक्ति की अपनी इच्छा के अनुसार जीवन का अंत, भारत में लंबे समय से सामाजिक, नैतिक और कानूनी विमर्श का विषय रही है। यह प्रश्न केवल मृत्यु से जुड़ा नहीं है, बल्कि असहनीय पीड़ा, मानवीय गरिमा, करुणा और आत्मनिर्णय के अधिकार से गहराई से संबंधित है। इनदिनों एक 32 वर्षीय युवक, जो पिछले 13 वर्षों से कोमा जैसी स्थिति में है, इस त्रासदी का जीवंत उदाहरण है। न चेतना, न संवाद, न सुधार की कोई संभावना, फिर भी परिवार भावनात्मक, मानसिक और आर्थिक यातना झेलने को विवश है। इस मामले ने एक बार फिर इच्छा मृत्यु के प्रश्न पर विमर्श का वातावरण बना दिया है। ऐसे हजारों मामले देशभर में चुपचाप पीड़ा सह रहे हैं, जिनका न तो कोई समाधान है और न ही कोई स्पष्ट कानूनी रास्ता। यह स्थिति केवल चिकित्सा संकट नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना और सामाजिक न्याय की गंभीर परीक्षा है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने जीवन को कृत्रिम रूप से लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता तो विकसित कर ली है, लेकिन यह तय नहीं कर पाया है कि जब जीवन केवल पीड़ा, चेतनाहीनता और निरर्थक जैविक क्रिया बन जाए, तब उसे ढोते रहना ही मानवता है या उसे सम्मानपूर्वक विदा देना अधिक करुणामय विकल्प है। विडंबना यह है कि जो लोग असाध्य बीमारी, लंबे कोमा या पूर्णतः चेतनाशून्य अवस्था में नारकीय जीवन जीने को विवश हैं, उनके लिए भारतीय कानून आज भी स्पष्ट और मानवीय मार्ग तय नहीं कर पाया है। ऐसे लोग यह मानते हैं कि जब जीवन से गरिमा, चेतना और आशा समाप्त हो जाए, तब जीवन की तुलना में गरिमापूर्ण मृत्यु अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

प्रश्न यह उठता है कि हमारा कानून ऐसी मृत्यु को आज भी संदेह, भय और अपराध की दृष्टि से क्यों देखता है? भारतीय दंड संहिता की धारा 309 और 306 लंबे समय तक इच्छा मृत्यु के मार्ग में कानूनी बाधा बनी रहीं। भले ही 2017 के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम में आत्महत्या के प्रयास को मानसिक पीड़ा का परिणाम मानते हुए अपराध की श्रेणी से आंशिक रूप से बाहर किया गया हो, लेकिन इच्छा मृत्यु के प्रश्न पर आज भी कोई समग्र और स्पष्ट कानून मौजूद नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, परंतु यह बहस आज भी जारी है कि क्या इसमें गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार अंतर्निहित है या नहीं? इच्छा मृत्यु को लेकर भारतीय न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मोड़ वर्ष 2011 में अरुणा शानबाग मामले में देखने को मिला। अरुणा शानबाग, जो मुंबई के केईएम अस्पताल में नर्स थीं, 1973 में हुए एक अमानवीय हमले के बाद मस्तिष्क क्षति का शिकार हो गई और 42 वर्षों तक परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट-यानी सतत् विकृतशील दशा में रहीं। उनकी ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सक्रिय इच्छा मृत्यु को अस्वीकार करते हुए यह स्वीकार किया कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को सशर्त अनुमति दी जा सकती है। न्यायालय ने माना कि यदि रोगी की स्थिति असाध्य है, चेतना लौटने की कोई संभावना नहीं

है और उपचार केवल जीवन को यांत्रिक रूप से खींच रहा है, तो विशेषज्ञों की राय और न्यायिक निगरानी में जीवन रक्षक उपचार हटाया जा सकता है। यह निर्णय भारतीय न्यायिक इतिहास में एक बड़ा कदम था, लेकिन यह भी स्पष्ट हो गया कि यह समाधान अपवाद था, स्थायी कानून नहीं।

इसके बाद 2018 में कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक टिप्पणी की कि जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन और गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी है। इसी फैसले में 'लिविंग विल' या 'एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव' को वैध माना गया, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति पहले से यह दर्ज कर सकता है कि असाध्य अवस्था में उसे जीवन रक्षक उपचार न दिया जाए। किंतु इस प्रक्रिया को इतनी जटिल औपचारिकताओं से बाँध दिया गया कि व्यवहार में यह अधिकार आम नागरिक के लिए लगभग अप्राप्य बनकर रह गया। हाल के वर्षों में ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं जो इस समस्या की भयावहता को उजागर करते हैं। इच्छा मृत्यु की आवश्यकता इसी यथार्थ से जन्म लेती है। असाध्य कैंसर, न्यूरोलॉजिकल रोगों और अंतिम अवस्था की बीमारियों में जीवन पीड़ा का पर्याय बन जाता है। चेतनाहीन शरीर को मशीनों के सहारे जीवित रखना जीवन कम और यातना अधिक प्रतीत होता है।

व्यक्ति को अपने जीवन के अंतिम निर्णय का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्णय लोकतांत्रिक समाज का मूल मूल्य है। लंबे समय तक चलने वाला उपचार परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ देता है और सीमित चिकित्सा संसाधनों का प्रश्न भी खड़ा करता है। इच्छा मृत्यु के विरोध में यह तर्क दिया जाता है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, बुजुर्गों या गरीबों पर दबाव बनाया जा सकता है और डॉक्टर जीवन-मृत्यु का निर्णयकर्ता बन जाएंगे। ये आशंकाएँ गंभीर हैं, किंतु इनका समाधान इच्छा मृत्यु को नकारने में नहीं, बल्कि स्पष्ट, सख्त और पारदर्शी कानून बनाने में है। अंतरराष्ट्रीय अनुभव बताते हैं कि जहां स्पष्ट कानून और बहुस्तरीय निगरानी व्यवस्था है, वहां दुरुपयोग की संभावना कम होती है। नीदरलैंड्स, बेल्जियम, कनाडा और स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों ने यह सिद्ध किया है कि करुणा और नियंत्रण साथ-साथ चल सकते हैं। वैसे भारत में भी जैन धर्म का संथारा (सल्लेखना) और आधुनिक संदर्भ में इच्छा मृत्यु दोनों पहली दृष्टि में समान प्रतीत होते हैं, किंतु दर्शन, उद्देश्य, प्रक्रिया और संवैधानिक व्याख्या के स्तर पर इनके बीच मौलिक अंतर भी हैं और कुछ गहरी समानताएँ भी। इसी कारण एक ही देश में संथारा निर्बाध चलता रहा है और इच्छा मृत्यु आज भी बहस का विषय बनी हुई है।

जैन धर्म में संथारा या सल्लेखना को मृत्यु नहीं, बल्कि जीवन की अंतिम साधना यानी मृत्यु का महोत्सव माना गया है। यह न तो पीड़ा से पलायन है और न ही जीवन से पलायन, बल्कि आसक्ति, क्रोध, भय और मोह के क्षय की आध्यात्मिक प्रक्रिया है। संथारा तब लिया जाता है जब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसका शरीर साधना के योग्य नहीं रहा, बीमारी असाध्य हो चुकी है, या वृद्धावस्था में देह शिथिल हो गई है। इसमें भोजन और जल का त्याग क्रमशः, संयमपूर्वक और गुरु की आज्ञा से किया जाता है। इसका उद्देश्य शरीर को नष्ट करना नहीं, बल्कि आत्मा को निर्मल करना होता है। जैन दर्शन में यह माना जाता है कि मृत्यु तो अनिवार्य है, प्रश्न केवल इतना है कि वह आसक्ति और व्याकुलता में हो या समता और सजगता में। इसके विपरीत इच्छा मृत्यु आधुनिक विधिक अवधारणा है, जिसका मूल उद्देश्य असहनीय शारीरिक या मानसिक पीड़ा से मुक्ति है। इसमें व्यक्ति यह चाहता है कि जीवन की यातना समाप्त हो जाए, क्योंकि चेतना, संवाद और सुधार की कोई संभावना नहीं बची है। यह निर्णय भावनात्मक, चिकित्सकीय और परिस्थितिजन्य होता है, न कि आध्यात्मिक साधना का अंग। इच्छा मृत्यु में दवा, इंजेक्शन या जीवन रक्षक प्रणाली हटाने जैसे भौतिक साधन जुड़े होते हैं, जबकि संथारा में हिंसा का कोई सक्रिय साधन नहीं होता।

अब समय आ गया है कि भारत भी इच्छा मृत्यु विषय पर संकोच छोड़कर स्पष्ट और मानवीय कानून बनाए। ऐसा कानून जो असाध्य और अपरिवर्तनीय स्थितियों की वैज्ञानिक पहचान करे, रोगी की इच्छा और गरिमा को सर्वोपरि माने, परिजनों को अनावश्यक पीड़ा से बचाए और डॉक्टरों को नैतिक तथा कानूनी सुरक्षा प्रदान करे। इच्छा मृत्यु जीवन के विरुद्ध नहीं, बल्कि अर्थहीन पीड़ा के विरुद्ध एक करुणामय विकल्प है। जब जीवन केवल मशीनों पर टिका एक जैविक क्रम बन जाए और चेतना, सम्मान व आशा समाप्त हो जाए, तब मृत्यु को अपराध नहीं, बल्कि मानवीय अधिकार के रूप में देखना होगा। यदि हमारा संविधान जीवन को गरिमा देता है, तो उसी गरिमा के साथ मृत्यु चुनने का अधिकार भी देना होगा। इच्छा मृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाना केवल कानूनी सुधार नहीं, बल्कि एक संवेदनशील, परिपक्व और करुणामय समाज की पहचान है। मानवीय करुणा की मांग है कि जीवन की पवित्रता और पीड़ा की करूरता के बीच संतुलन बनाया जाए। इच्छामृत्यु जब सहमति से होगी तो मानवता को कायम रखा जा सकता है। न्यायपालिका को ऐसा न्याय देना चाहिए, जो रोगी को पीड़ा से मुक्त करे और एक करुणामय भविष्य का मार्ग प्रशस्त करे।

नए भारत के बढ़ते कदमां के पीछे वैचारिक प्रबुद्धता, योजना और समेकित दृढ़ संकल्प

संजीव ठाकुर

यह भारत के बढ़ते कद के नेपथ्य में कुशल नेतृत्व, सामूहिक चेतना और प्रगतिशील विचारों की उस दीर्घ साधना का फल है, जिसकी जड़ें इतिहास में हैं और शाखाएँ भविष्य तक फैली हुई हैं, भारत आज विश्व-पटल पर केवल एक उभरती शक्ति नहीं बल्कि एक ऐसी निर्णायक उपस्थिति बन चुका है। जिसे अनदेखा करना किसी भी राष्ट्र के लिए संभव नहीं रहा, यह काल किसी एक सरकार, एक व्यक्ति या एक विचारधारा का नहीं बल्कि उस राष्ट्रीय चेतना का है जो सदियों के आत्मसंघर्ष, आत्मचिंतन और आत्मबल से परिपक्व हुई है, मैं स्वयं को किसी राजनीतिक दल का समर्थक नहीं मानता, किंतु यह तथ्य निर्विवाद है कि आज भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा, कूटनीतिक प्रभाव और आत्मविश्वास ऐतिहासिक ऊँचाइयों को छू रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणों में भारतीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का आँकड़ा किसी व्यक्ति की प्रशंसा भर नहीं बल्कि उस विश्वास का प्रमाण है जो विश्व समुदाय भारत की स्थिरता, लोकतांत्रिक परिपक्वता और विकास-दृष्टि पर कर रहा है, महात्मा गांधी ने कहा था कि ÷राष्ट्र की वास्तविक पहचान उसकी आत्मा से होती है,÷ और आज भारत की आत्मा विज्ञान, तकनीक, करुणा, सहअस्तित्व और नवाचार के संतुलन से आलोकित दिखाई देती है, डिजिटल इंडिया के माध्यम से जिस प्रकार भारत ने तकनीक को अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुँचाया है वह केवल प्रशासनिक सफलता नहीं बल्कि लोकतंत्र के विस्तार की ऐतिहासिक घटना है, विश्व बैंक, आईएमएफऔर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों में भारत को विकासशील देशों के लिए प्रेरणा बताया जाना इस बात का संकेत है कि भारत अब सीखने वाला नहीं बल्कि मार्ग दिखाने वाला राष्ट्र बन चुका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के समय कहा था कि ÷हम नियति से साक्षात्कार कर रहे हैं,÷ और आज वह साक्षात्कार एक नए रूप में हमारे सामने खड़ा है, 1951 से आरंभ पंचवर्षीय योजनाओं ने जिस नियोजनशील दृष्टि को जन्म दिया, 1991 के आर्थिक सुधारों ने उसे वैश्विक पंख दिए और नीति आयोग ने उसे नवाचार व प्रतिस्पर्धा की नई दिशा प्रदान की, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का यह कथन कि ÷विकास का अंतिम उद्देश्य मानव स्वतंत्रता का विस्तार है,÷ भारत की विकास यात्रा में सजीव होता दिखाई देता है, विशाल जनसंख्या जिसे कभी बोझ कहा जाता था आज वही भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरी है, स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को राष्ट्र की रीढ़ बताते हुए कहा था कि ÷उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत,÷ और भारत की युवा शक्ति आज इसी मंत्र को वैश्विक मंच पर चरितार्थ कर रही है, आईटी, सॉफ्टवेयर, अंतरिक्ष, जैव-प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप संस्कृति में भारत की छलांग यह प्रमाणित करती है कि यह देश केवल संसाधनों का उपभोक्ता नहीं बल्कि विचारों का उत्पादक बन चुका है, सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, इंदिरा नूई, अरविंद कृष्णा जैसे वैश्विक नेतृत्वकर्ता भारतीय मस्तिष्क की उसी परंपरा के वाहक हैं जिसे आचार्य चाणक्य ने नीति और विवेक का आधार बताया था, उद्योग जगत में टाटा, अंबानी और मित्तल जैसे नाम यह सिद्ध करते हैं कि भारतीय उद्यमिता अब आत्मविश्वास के साथ विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रही है, रतन टाटा के शब्दों में ÷जोखिम उठाए बिना प्रगति असंभव है,÷ और भारत ने अब जोखिम से भय नहीं बल्कि अवसर का निर्माण करना सीख लिया है, रक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में पोखरण से लेकर अंतरिक्ष अभियानों तक भारत की उपलब्धियाँ उस वैज्ञानिक चेतना का प्रमाण हैं जिसे डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने ÷विकसित भारत का सपना÷ कहा था, असैन्य परमाणु समझौते और रणनीतिक साझेदारियों ने यह स्थापित किया कि भारत विश्व शांति और संतुलन का उत्तरदायी भागीदार है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत की बहुस्तरीय कूटनीति–चाहे वह अमेरिका हो, रूस, जापान, फ्रांस, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया–वसुधैव कुटुम्बकम् की उस भावना को साकार करती है जिसे भारतीय दर्शन ने सहस्राब्दियों पहले उद्घोषित किया था, दावोस में विश्व आर्थिक मंच से लेकर जी-20 जैसे वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका यह संकेत देती है कि यह देश अब केवल प्रतिक्रियाशील नहीं बल्कि दिशा-निर्देशक बन चुका है, सैमुअल हंटिंगटन का यह कथन कि इक्कीसवीं सदी का संतुलन एशिया में तय होगा, आज भारत-केंद्रित होता प्रतीत हो रहा है, जनसांख्यिकीय लाभ, तीव्र जीडीपी वृद्धि और नवाचार की गति भारत को दीर्घकालीन स्थिरता प्रदान कर रही है, लोकतंत्र जिसकी जड़ें ग्रामसभा से लेकर संसद तक फैली हैं आज विश्व के लिए एक जीवंत उदाहरण है कि विविधता कैसे शक्ति बनती है, डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान को सामाजिक न्याय का औजार बताया था और आज वही संविधान भारत की प्रगति का नैतिक आधार बना हुआ है, साहित्य, संस्कृति और विचार के क्षेत्र में भी भारत की उपस्थिति सशक्त है, नोबेल विजेता रामकृष्णन से लेकर अमर्त्य सेन तक और वैश्विक साहित्य में भारतीय मूल के लेखकों की स्वीकार्यता यह दर्शाती है कि भारत की आवाज केवल आर्थिक नहीं बल्कि वैचारिक भी है, रवींद्रनाथ ठाकुर ने जिस विश्वमानव की कल्पना की थी आज भारत उसी विचार का वाहक बनता दिखाई दे रहा है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि भारत अब केवल भविष्य का स्वप्न नहीं बल्कि वर्तमान की सशक्त वास्तविकता है, यह स्वर्णिम काल तभी सार्थक रहेगा जब यह विकास करुणा, समावेशिता और नैतिकता से जुड़ा रहेगा, क्योंकि जैसा कि महात्मा गांधी ने चेताया था, ÷नैतिकता के बिना प्रगति विनाश का कारण बन जाती है,÷ आज भारत के उत्थान की यह गाथा विश्व को यह संदेश दे रही है कि शक्ति का अर्थ प्रभुत्व नहीं बल्कि उत्तरदायित्व है, और इसी उत्तरदायित्व के साथ भारत वैश्विक मंच पर विचार, तकनीक और कूटनीति का सूत्रधार बनकर उभरा है, जहाँ से यह उद्घोष सुनाई देता है कि भारत अब भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान का नेतृत्व कर रहा है। **यह निजी विचार है।**

मैकाले के बच्चे ही आज भी भारत के बिल भर रहे

सतीश झा

भारत की एकमात्र अनलूटेबल संपत्ति वह पतली परत है–अंग्रेज़ी-फ्लुएंट, विश्लेषणात्मक रूप से प्रशिक्षित दिमाग़ों की–जिसे मैकाले ने जन्म दिया था। बाकी कोयला, खनिज, नदियाँ–हमने ही चुरा लिए, बर्बाद किए, या लाल फ़ीते में कसकर बांध दिए। इतना सब होने के बावजूद हमने इसके साथ क्या किया? लगभग कुछ नहीं–बल्कि उल्टा किया।

एक असहज सच है, जिसे बोलते ही या लिखते ही कथित देशभक्त व्हाट्सऐप ग्रुप का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। पर सच से आँख चुराने का कोई फ़ायदा नहीं है। आधुनिक भारत आज भी उसी ईंधन पर चल रहा है, जिसे 1835 में थॉमस बैबिंगटन मैकाले ने हमारी नसों में उतारा था। यह कोई अकादमिक तर्क नहीं, यह जमीन की वह कठोर हकीकत है।

और यह हकीकत बताती है कि आईटी एक्सपोर्ट से लेकर फार्मा पेटेंट तक, रिज़र्व बैंक से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं से लेकर वैश्विक स्टार्ट-अप बोर्डरूम तक–भारत की जो भी आधुनिक मशीनरी चल रही है, उसका अस्सी फ़ीसदी इंजन उसी अंग्रेज़ी शिक्षा और विश्लेषणात्मक प्रशिक्षण से पनपा जिसे मैकाले ने अपने मिनटया कि नोट में दर्ज किया था।

मैकाले तब महज़ 34 साल का था, भारत में चार साल भी पूरा नहीं काट पाया, फिर भी उसने कॉलोनी को बदल देने वाली वह अवधारणा गढ़ दी जिसने आगे चलकर पूरे राष्ट्र, भारतीयों के के बौद्धिक खाके को आकार दिया।

मैकाले ने साफ कहा था कि उसे ऐसी प्रशासकीय जाति चाहिए जो खून और रंग से भारतीय भले हो पर स्वाद, विचार, चरित्र और बुद्धि से अंग्रेज़। उसने जो माँगा, इतिहास ने वैसा ही बना दिया। आज हमारे बौद्धिक पिरामिड की ऊपर की 15ङ्क20 प्रतिशत परत–जिसे आप चाहें तो मैकाले के बच्चे कह लें वह भारत का सबसे ज़्यादा टैक्स उत्पन्न करती है, ज़्यादातर फॉरेन एक्सचेंज कमाती है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की लगभग सारी उपलब्धियों को आकार देती है, और दुनिया में भारत की साख का सबसे बड़ा जनक है।

बाकी 80 प्रतिशत मेहनतकश भारत पर इसका कोई मान नहीं; यह उस आर्थिक सच्चाई का नाम है जिसमें हम अभी भी रहते हैं। वह सच्चाई यह है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय आज भी बोत्सवाना और गैबन जैसे देशों से कम है–वे देश जो तेल, हीरों और प्राकृतिक संपदा के महासागरों पर टिके हैं, जबकि हम दुनिया की सबसे कम उपयोग की गई मानवीय प्रतिभा पर टिके हैं।

मैकाले के आलोचक सदैव रहे–गांधी की पीढ़ी से लेकर आज की सत्ता तक। और वे एक बिंदु बिल्कुल ठीक उठाते हैं- यह शिक्षा-प्रणाली नवोन्मेषी दिमाग़ नहीं बनाती, बल्कि एक क्लर्की जाति बनाती थी और है। यह भारतीय भाषाओं की प्रतिभा को दबा गई; इसने शिक्षा को ज्ञान की बजाय सामाजिक प्रतिष्ठा का टोकन बना दिया; और पीढ़ियों को पश्चिमी मान्यता के लिए लालायित कर दिया।

यह सब सच है। लेकिन आलोचक यहीं रुक जाते हैं, जबकि वाक्य अधूरा इसी वजह से रह जाता है कि वे यह नहीं कहते कि–यदि यह ढांचा न होता तो क्या होता?

सचाई यह है कि यदि मैकाले की वह प्रशासनिक रीढ़ न होती, तो 1947 में 28 रियासतों और 565 जागीरों वाला यह उपमहाद्वीप एक गणराज्य के रूप में एकसाथ खड़ा ही नहीं हो पाता। हमारे पास बॉम्बे प्लान जैसी औद्योगिक कल्पना लिखने वाले अभियंता नहीं होते, 1974 में परमाणु परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक नहीं होते, और 1991 में अपने ही संकट से जूझते हुए आईएमएफ को ठोस अंग्रेज़ी तर्कों के साथ यह मनाने वाले अर्थशास्त्री नहीं होते कि भारत को सांस लेने दीजिए, हम अपनी अर्थव्यवस्था को खोलेंगे।

गणतंत्र दिवस पर जिस भी उपलब्धि का हम झंडा उठाते हैं, उसकी कहानी को ध्यान से पढ़िए–आप पाएँगे कि उसके लेखक, उसके तकनीकी दिमाग, उसके मुख्य संचालक, वे ही थे जिन्हें मैकाले ने कभी अपनी प्रशासकीय जाति के लिए कल्पना किया था।

ज़रा दुनिया के नक्शे में एक और उदाहरण देखिए। अफ्रीका में भारत के मुकाबले दस गुना अधिक खनिज-संपदा है, दो गुना ज़मीन है, और वहाँ उपनिवेशी भाषाई दखल भी भारत जितना गहरा नहीं था। फिर भी उप-सहारा अफ्रीका की प्रति व्यक्ति आय भारत से अधिक है। क्यों? क्योंकि खनिज और प्राकृतिक संपदा को तानाशाह और ताकतवर लूट सकते हैं; मानव पूंजी को कोई नहीं लूट सकता।

भारत की एकमात्र अनलूटेबल संपत्ति वह पतली परत है–अंग्रेज़ी-फ्लुएंट, विश्लेषणात्मक रूप से प्रशिक्षित दिमाग़ों की–जिसे मैकाले ने जन्म दिया था। बाकी कोयला, खनिज, नदियाँ–हमने ही चुरा लिए, बर्बाद किए, या लाल फ़ीते में कसकर बांध दिए।

इतना सब होने के बावजूद हमने इसके साथ क्या किया? लगभग कुछ नहीं–बल्कि उल्टा किया। **यह निजी विचार है।**

अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन : राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 20-21 दिसंबर को धुलिया में

प्री वेडिंग शूट, हम पांच योजना, अग्र अलंकरण, शैक्षणिक प्रोत्साहन, पंचायत समिति गठन, वैवाहिक बायोडाटा केंद्र, जैसे ज्वलंत मुद्दों पर होंगे निर्णय - डॉ अशोक अग्रवाल

लोकशक्ति

कुलभूषण मित्तल कुकी
राष्ट्रीय अध्यक्ष , अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन

अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन आगामी 20 एवं 21 दिसंबर 2025 को महाराष्ट्र के धुलिया शहर में किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन संगठन के राष्ट्रीय चेयरमैन श्री प्रदीप मित्तल के सानिध्य में तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुलभूषण मित्तल की अध्यक्षता में होगा।

अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ अशोक अग्रवाल एवं राष्ट्रीय महामंत्री श्री राजेश भारुका, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रामबाबू सिंघल ने जानकारी देते हुए बताया कि, इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में समाजोपयोगी विषयों पर गहन मंथन एवं समीक्षा की जाएगी। साथ ही संगठन के भविष्य की दिशा तय करने हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह बैठक धुलिया अग्रवाल समाज एवं महाराष्ट्र राज्य अग्रवाल सम्मेलन के आतिथ्य में आयोजित की जा रही है।

बैठक में देशभर के सभी प्रांतों से प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य तथा विशेष आमंत्रित सदस्य उपस्थित रहेंगे।

राष्ट्रीय संरक्षक श्री सियाराम अग्रवाल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ से 21 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल इस मीटिंग में सम्मिलित होने के लिए 19 तारीख को प्रस्थान कर रहा है, सियाराम अग्रवाल, महेंद्र सेक्सरिया, जयदेव सिंघल नेतराम अग्रवाल ने बताया कि, इस दो दिवसीय बैठक में मुख्य रूप से, नव नियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष का शपथ ग्रहण एवं उद्बोधन होगा, तत्पश्चात समाज के कुछ महत्वपूर्ण विषय जैसे

विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए वैवाहिक बायोडाटा बैंक प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर, विवाह योग्य बच्चों के बायोडाटा बैंक बनाने पर चर्चा और निर्णय।

प्री वेडिंग शूट बंद करने के अभियान की प्रगति पर चर्चा - श्री अग्रसेन कन्या विवाह योजनाः मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए सीमित खर्चों पर विवाह संपन्न करने की योजना पर चर्चा एवं निर्णय

अग्र पंचायत समिति का गठनः समाज में विवाह संबंधों में हो रहे संबंध विच्छेद एवं अन्य सामाजिक विवादों के निराकरण के लिए राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तरों पर गठन सामाजिक एवं धार्मिक आयोजन सामूहिकता की भावना से किए जाने पर चर्चा (सामूहिक तुलसी विवाह, ग्यारस उद्यापन,ऋषि पंचमी,पूनम उद्यापन,गया श्राद्ध,भागवत कथा एवं अन्य प्रचलित धार्मिक रीति रिवाज) **हम पांच योजना :** (2 से अधिक बच्चों के जन्म पर दंपतियों को पुरस्कृत करना) अग्र अलंकरण समारोहः समाज के प्रतिभावान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाले शख्सियतों का सम्मान जैसे अनेक विषय हैं , जिन पर पूरे राष्ट्र से आए हुए अग्रबंधु गहन विचार विमर्श कर निर्णय लेंगे। इस दौरान आगामी समय में अग्रवाल संगठन द्वारा किए जाने वाले सामाजिक, शैक्षणिक एवं संगठनात्मक कार्यों की रूपरेखा भी तय की जाएगी। आयोजन समिति के सदस्य श्री रमाकांत खेतान, श्री गोपाल अग्रवाल, श्री विनोद अग्रवाल, श्री किरण अग्रवाल, श्री विजय चौधरी श्री पवन मित्तल एवं श्री कैलाशचंद्र अग्रवाल ने बताया कि, इस राष्ट्रीय बैठक को लेकर प्रदेशभर के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। आयोजन समिति कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे उत्साह और समर्पण के साथ तैयारियों में जुटी हुई है।

20 दिसंबर 2025 को शहीद वीर नारायण सिंह शहादत दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा

एजेंसी

शहीद वीर नारायण सिंह शहादत दिवस का 20 दिसंबर में आयोजन। मुड़ा क्षेत्र सिंग पुर एवं जिला गोंड महासभा राजनांदगांव के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश में सिंग पुर स्कूल ग्राउंड के पास 20 दिसंबर 2025 को शहीद वीर नारायण सिंह शहादत दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉ रमन सिंह जी अध्यक्ष विधानसभा छः ग शासन होंगे जबकि अध्यक्षता माननीय गजेन्द्र यादव जी शिक्षा मंत्री कैबिनेट छः ग शासन करेंगे विशेष अतिथि श्री नीलकंठ गढ़े जिला गोंड महासभा राजनांदगांव सदस्य वन जीव बोर्ड छः ग शासन सीता राम ठाकुर कोमल सिंह राजपूत जिला अध्यक्ष भाजपा राजनांदगांव होंगे प्रायोजित कार्यक्रम में आमंत्रण हेतु नीलकंठ गढ़े जी के नेतृत्व में विधान सभा अध्यक्ष निवास कार्यालय में जितेंद्र पटौदी चोवा मंडावी गुरुदेव पटौदी नौकेश पटौदी सीताराम ठाकुर जीवन दीप समिति के आजीवन सदस्य दिलीप ठाकुर सम्मिलित हुए जिला अध्यक्ष गोंड महासभा राजनांदगांव बतलाए रिलो नृत्य के द्वारा मुख्य अतिथि एवं आमंत्रित अतिथियों का स्वागत सम्मान होगा पश्चात आयोजन प्रभारी के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत होगा अतिथियों के संबोधन अंत में आभार प्रदर्शन स्वागत सम्मान सुर संध्या सांस्कृतिक कार्यक्रम नृत्य कार्यक्रम भी आयोजित होगा।

भूजल विशेषज्ञ ने महाराजबंध तालाब के पानी को बताया उपयोग योग्य नहीं, छठे दिन भी जारी रहा ग्रीन आर्मी का सफाई अभियान

(भूजल विशेषज्ञ, डिप्टी कमिश्नर, जोन कमिश्नर एवं जनप्रतिनिधियों ने किया महाराजबंध का निरीक्षण)

रायपुर। संवाददाता

ऐतिहासिक महाराजबंध तालाब को बचाने ग्रीन आर्मी छत्तीसगढ़ का सफ ई अभियान छठे दिन भी निरंतर जारी रहा। तालाब के जलक्षेत्र एवं किनारों से प्लास्टिक, पॉलीथिन, विसर्जन सामग्री और गाद हटाकर सफाई कार्य किया गया। अभियान के दौरान भूजल विशेषज्ञ श्री पाणिग्रही द्वारा तालाब के पानी का नमूना जांच हेतु लिया गया। प्रारंभिक निरीक्षण में उन्होंने बताया कि तालाब के पानी में मछलियों के मरने के संकेत मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान स्थिति में यह पानी उपयोग योग्य नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि पानी की शासकीय प्रयोगशाला में विधिवत जांच कराई जाएगी तथा जांच रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय सहित राज्य शासन एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को प्रस्तुत की जाएगी।

छठे दिन नगर निगम डिप्टी कमिश्नर श्री विनोद पांडे, जोन-6 कमिश्नर श्री हितेंद्र यादव, महंत लक्ष्मीनारायण दास वार्ड के पार्षद श्री अम्बर अग्रवाल एवं महामाया मंदिर वार्ड के पार्षद श्री नायक स्थल पर पहुँचे और सफाई कार्यों का अवलोकन किया।

प्रदेश अध्यक्ष अमिताभ दुबे ने कहा कि महाराजबंध तालाब की वर्तमान स्थिति अब पर्यावरण और जनस्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय बन चुकी है। समय रहते ठोस और स्थायी कदम उठाया जाना आवश्यक है, ताकि इस ऐतिहासिक तालाब को भविष्य में सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि ग्रीन आर्मी जनसहयोग से यह अभियान चला रही है और प्रशासनिक मार्गदर्शन व संसाधनों की उपलब्धता से कार्य और अधिक प्रभावी हो सकता है।

प्रदेश मीडिया प्रभारी शशिकांत यदु ने कहा कि भूजल विशेषज्ञ की प्रारंभिक रिपोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तालाब संरक्षण अब टाला नहीं जा सकता। शासकीय लैब से आने वाली जांच रिपोर्ट के आधार पर ग्रीन आर्मी आगे की रणनीति तैयार करेगी और शासन-प्रशासन के समक्ष तथ्यात्मक रूप से अपनी बात रखेगी। अभियान में स्थानीय नागरिकों, युवाओं, सामाजिक संगठनों के साथ-साथ महिला शक्ति की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, जिससे यह मुहिम एक व्यापक जनआंदोलन का रूप लेती जा रही है। ग्रीन आर्मी ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान से जुड़कर रायपुर की इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाएँ।

जेम एक्सीलेंस समिट 2025 : वर्कफ़्लो का अधिक प्रभावी और दक्ष सक्षम बनाना

एजेंसी

गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जेम) द्वारा छत्तीसगढ़ के खरीदारों और विक्रेताओं के लिए ÷जेम एक्सीलेंस समिट 2025÷ का आयोजन 19 दिसंबर 2025, पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस, रायपुर में किया जा रहा है। इस समिट का उद्देश्य राज्य के सभी विभागों में डिजिटल सार्वजनिक खरीद की क्षमता को मजबूत करना और खरीदार संगठनों को जेम के ईकोसिस्टम, प्रमुख सुविधाओं और वर्कफ़्लो का अधिक प्रभावी और दक्ष उपयोग करने में सक्षम बनाना है। समिट में राज्य के विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए उपलब्ध विविध अवसरों को विस्तार से साझा किया जाएगा। इस अवसर के माध्यम से वे स्थानीय इकाइयों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के खरीदार संगठनों तक एक ही डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर सरलता और पारदर्शिता के साथ पहुँच बना सकेंगे।

हाल ही में जेम द्वारा काशन मनी की समाप्ति और वेंडर असेसमेंट शुल्क में कमी ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स, कारीगरों और स्ट/स्ज्ञ उद्यमियों की भागीदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। इन कदमों ने सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया को पहले की तुलना में कहीं अधिक सुलभ, पारदर्शी और अवसरों को सृजन करने वाला बनाया है। यह परिवर्तन विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।

समिट के संबंध में जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मिहिर कुमार ने कहा कि यह कार्यक्रम राज्य के खरीदारोम एवं विक्रेताओं के लिए नई सुविधाओं को समझने, संचालन प्रक्रियाओं पर स्पष्टता प्राप्त करने तथा रचनात्मक सुझाव साझा करने का एक सशक्त मंच प्रदान करेगा। उनके अनुसार, यह समिट छत्तीसगढ़ को पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और दक्ष सार्वजनिक खरीद के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

छत्तीसगढ़ द्वारा जेम के माध्यम से अब तक ?6,408 करोड़ से अधिक मूल्य की वस्तुएँ और सेवाएँ खरीदी जा चुकी हैं। इनमें से ?2,600 करोड़ की खरीद छत्तीसगढ़ के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से हुई है, जो राज्य की समावेशी खरीद के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

जेम ने राज्य में खरीद प्रक्रिया को तेज़ बनाने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, पूरे देश के बाज़ार तक पहुँच उपलब्ध कराने और हर खरीद फैसले को पूरी तरह पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जेम छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर डिजिटल गवर्नेंस और समावेशी खरीद प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' से बदली तकदीर, आत्मनिर्भरता की बनी मिसाल

लखपति दीदी' बनीं संजुलता सेठ, सैकड़ों महिलाओं के लिए बनीं प्रेरणा

रायपुर,संवाददाता।

बिहान योजना के अंतर्गत स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद संजुलता सेठ ने सब्जी उत्पादन, सिलाई कार्य एवं बैग निर्माण जैसी विभिन्न आजीविका गतिविधियों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के साथ-साथ उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहयोग भी मिला, जिससे उन्होंने इन गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से अपनाया और आय का स्थायी साधन बनाया।

स्व-सहायता समूह बना आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव

रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड के ग्राम पंचायत तरडा की रहने वाली संजुलता सेठ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) 'बिहान' से जुड़कर आज क्षेत्र में ÷लखपति दीदी÷ के रूप में अपनी सशक्त पहचान बना चुकी हैं। केवल खेती पर निर्भर रहने वाली संजुलता सेठ का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रही थी द्य सीमित आय के कारण बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और घरेलू जरूरतों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे कठिन समय में उन्होंने समृद्धि स्व-सहायता समूह से जुड़ने का निर्णय लिया, जिसने उनके जीवन को नई दिशा और नई उड़ान दी।

आर्थिक मजबूती की सशक्त कहानी जहां पहले कृषि कार्य से उनकी सालाना आय मात्र 55 हजार रुपये थी, वहीं स्व-सहायता समूह के माध्यम से 3 लाख रुपये का बैंक ऋण प्राप्त कर उन्होंने अपने व्यवसायों का विस्तार किया। आज वे विभिन्न आजीविका गतिविधियों से लगभग 1 लाख 65 हजार रुपये की वार्षिक आय अर्जित कर रही हैं और अपने परिवार को सम्मानजनक जीवन दे पा रही हैं।

नदी और जलधाराओं से गाद निकालने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय योजनाएँ

पीआईबी

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जलाशय अवसादन सहित नदियों, जलधाराओं में गाद के व्यापक और समग्र प्रबंधन हेतु एक ÷राष्ट्रीय गाद प्रबंधन ढांचा (एनएफ्एसएम), अक्टूबर 2022÷ प्रकाशित किया गया है। इसमें गाद हटाने के बजाय गाद के उत्पादन को कम करने पर जोर दिया गया है।

एनएफ्एसएम पंजाब सहित देश के सभी नदी बेसिनों में गाद प्रबंधन संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु एक मार्गदर्शक दस्तावेज है और यह राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, मंत्रालयों और विभागों जैसे विभिन्न हितधारकों को पर्यावरणीय और पारिस्थितिक कारकों को ध्यान में रखते हुए रणनीतियां तैयार करने और परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में सहायता प्रदान करता है। एनएफ्एसएम में केंद्रीय एजेंसियों के विभागों/मंत्रालयों द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों/अधिसूचनाओं द्वारा दिए गए प्रासंगिक संदर्भ भी शामिल हैं।

नदियों से गाद निकालना बाढ़ नियंत्रण का तकनीकी रूप से व्यवहार्य समाधान नहीं माना जाता है, क्योंकि यह बाढ़ की तीव्रता को मामूली रूप से कम कर सकता है और यह केवल थोड़े समय के लिए ही प्रभावी है। स्थानीय साइट की स्थिति के आधार पर कभी-कभी ज्वारीय नदियों, संकरे स्थानों वाले संगम स्थलों आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों से चुनकर गाद निकालना पड़ सकता है; हालांकि, इसके लिए उचित वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है। बाढ़ प्रबंधन एवं कटाव-रोधी योजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित किया जाता है। केंद्र सरकार, राज्यों को तकनीकी मार्गदर्शन और गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन हेतु प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों में सहायता करती है।

भारत सरकार, नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी उपाय, जल निकासी विकास, समुद्र कटाव-रोधी उपाय आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने हेतु ÷बाढ़ प्रबंधन एवं सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम (एफ्एमबीएपी)÷ कार्यान्वित कर रही है। इस योजना की शुरुआत से अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 8737.66 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की जा चुकी है, जिसमें पंजाब राज्य सरकार को दी गई 67.51 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता भी शामिल है। यह सूचना केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी आर पाटिल द्वारा राज्यसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में प्रदान की गई है।

संयुक्त अरब अमीरात के प्रेसिडेंशियल गार्ड के कमांडर मेजर जनरल अली सैफ हुमैद अलकाबी ने नई दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की।

छत्तीसगढ़ सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर जिले में प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में संभाग आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग के सभी कलेक्टर की ली बैठक

पद्मश्री श्री अनुज शर्मा देंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति

संवाददाता।

कलेक्टर-एसपी ने किया कार्यक्रम स्थल निरीक्षण

जांजगीर-चांपा / छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 22 दिसम्बर 2025 को जिले में प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर संभागायुक्त श्री सुनील कुमार जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिलासपुर संभाग के सभी कलेक्टर की बैठक लेकर आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कार्यक्रम को गरिमामय, सुव्यवस्थित एवं सफल बनाने के लिए समयबद्ध ढंग से सभी व्यवस्थाएं पूर्ण करने कहा। संभागायुक्त ने मंच, बैठक व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, साफ-सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की। साथ ही उन्होंने पार्किंग स्थलों की व्यवस्था, आगंतुकों के लिए रूट चार्ट, वीआईपी मूवमेंट, हेलिपैड की तैयारी तथा सुरक्षा व्यवस्था की भी जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पद्मश्री श्री अनुज शर्मा द्वारा सांस्कृति कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे एवं पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पांडेय ने आज कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित समय-सीमा में सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि कार्यक्रम सफलतापूर्वक एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी तत्परता के साथ करें। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री गोकुल रावटे, अपर कलेक्टर श्री ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर, एडिशनल एसपी श्री उमेश कश्यप, एडिशनल एसपी श्री उदयन बेहार, संयुक्त कलेक्टर श्री संदीप सिंह ठाकुर सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

जिले में रोजगार मेला का आयोजन, निजी क्षेत्र के नियोजको द्वारा 266 पदों पर होगी भर्ती

जांजगीर-चांपा / कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन में जिले के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के कुल 07 नियोजक भाग लेंगे, जिनके माध्यम से लगभग 266 पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने बताया कि रोजगार मेला में निजी क्षेत्र के नियोजको द्वारा मेटलर्जी इंजीनियर, ट्रेलर ड्राइवर, जनरल मैनेजर (मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल), आईटीआई टर्नर, मशीनिस्ट, हेड एनवायरनमेंट, हेड सस्टेनेबिलिटी, बॉयलर डीसीएस इंजीनियर, बॉयलर फील्ड ऑपरेटर, टरबाइन डीसीएस इंजीनियर, शिफ्ट इंजीनियर आदि पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में सिक्योरिटी गार्ड, फील्ड ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर, हेल्थ एडवाइजर, बीमा सखी (ग्रामीण बीमा अभिकर्ता) जैसे पदों पर भी भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र के पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता बी.ई./बी.टेक./आईटीआई, जबकि अन्य पदों हेतु 10वीं, 12वीं एवं स्नातक निर्धारित की गई है।

कब और कहां लगेगा रोजगार मेला

17 दिसम्बर 2025 को जनपद पंचायत अकलतरा कृषि उपज मंडी प्रांगण, मुरलीडीह रोड, अकलतरा में, 26 दिसम्बर 2025 को जनपद पंचायत बलौदा के समरसता भवन, ग्राम पंचायत जावलपुर में, 07 जनवरी 2026 को जनपद पंचायत पामगढ़ के सद्भावना भवन, पामगढ़ में 16 जनवरी 2026 को जनपद पंचायत बम्हनीडीह के शासकीय हाई स्कूल भवन, ग्राम पंचायत कपिस्दा, बम्हनीडीह में एवं 28 जनवरी 2026 जनपद पंचायत नवागढ़ को स्कूल संगठन भवन, ग्राम पंचायत खैरताल (जी.एल.डी.), स्कूल केरा रोड, नवागढ़ में रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। जिले के इच्छुक युवा जो रोजगार मेले में भाग लेना चाहते हैं, वे अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन कार्ड, आधार कार्ड सहित निर्धारित तिथि एवं स्थान पर उपस्थित हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय, जांजगीर-चाम्पा से संपर्क किया जा सकता है।

कलेक्टर जन्मेजय महोबे की अध्यक्षता में पल्स पोलियो अभियान के संबंध में जिला कार्यबल बैठक आयोजित

जांजगीर-चांपा / कलेक्टर जन्मेजय महोबे की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला कार्यबल की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने कहा जिले में राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियों अभियान 21 दिसम्बर 2025 से शुरू होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राजस्व, महिला बाल विकास, शिक्षा विभाग, मितानिनों, ग्राम के कोटवार, निजी चिकित्सालय, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से कार्यक्रम को सफल बनाये। उन्होंने कहा राज्य, जिला, विकासखण्ड व सेक्टर स्तर के अधिकारी द्वारा पल्स पोलियो अभियान का सतत् मॉनिटरिंग किया जायेगा। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे सभी अभिभावकों से अपील हैं कि शून्य से 05 साल तक के सभी बच्चों को 21 दिसम्बर 2025 को पोलियों वैक्सीन की दो बूंद की खुराक अवश्यक पिलायें।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियों अभियान 21 दिसम्बर 2025 से शुरू होगा। तीन दिवसीय इस अभियान में जांजगीर जिले के 0 से 05 वर्ष तक के 1 लाख 53 हजार 914 बच्चों को पोलियों खुराक दी जाएगी। अभियान के पहले दिन 21 दिसम्बर को बुथ स्तर पर एवं 22 तथा 23 दिसम्बर 2025 को बुथ गतिविधियों में छुटे हुए बच्चों को टीकाकरण टीम के द्वारा गृह भेंट कर पोलियों की खुराक पिलाकर प्रतिरक्षित किया जाएगा। उन्होंने जिले में 960 बुथ बनाए गए जिसमें ग्रामीण स्तर में 795, शहरी स्तर में 165 तथा ट्रांजिट दल 21 एवं मोबाईल दल 10 बनाए गये हैं। जिसमें कुल 3840 वैक्सीनेटर एवं 192 पर्यवेक्षक उक्त अभियान में कार्य सम्पादित किया जाएगा। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री गोकुल रावटे, अपर कलेक्टर श्री ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर, अपर कलेक्टर श्री आर के तंबोली, संयुक्त कलेक्टर श्री संदीप सिंह ठाकुर, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती स्निग्धा तिवारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ यू के मरकाम, डीपीएम श्री उत्कर्ष तिवारी सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

कलेक्ट महोबे के निर्देशन में अवैध धान पर लगातार कार्रवाई जारी

मंडी अधिनियम के तहत सख्ती, 225 कट्टी (90 क्विंटल) धान जप्त

जांजगीर-चांपा ।कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन में जिले में अवैध धान पर मंडी अधिनियम के तहत लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज राजस्व,खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न ग्रामों में अवैध धान भंडारण के मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 225 कट्टी (90 क्विंटल) धान जप्त किया गया। कार्रवाई के दौरान ग्राम अर्जुनी में प्रमोद कुमार बंजारे से 70 कट्टी (28 क्विंटल),ग्राम बनहिल में कमल किशोर से 93 कट्टी (37.20 क्विंटल),ग्राम कटघरी में जयप्रकाश नायक से 32 कट्टी (12.80 क्विंटल),ग्राम पंतोरा बलौदा में विनोद मरावी से 30 कट्टी (12 क्विंटल) अवैध धान जप्त किया गया।

जिला समन्वयक एवं संकाय सदस्य के संविदा पद पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित

जांजगीर-चांपा / पंचायत संचालनालय अंतर्गत Revamped राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत जिले में रिक्त संविदा पदों जिला समन्वयक एवं संकाय सदस्य, जिला पंचायत संसाधन केन्द्र पर भर्ती हेतु 29 दिसम्बर 2025 तक सायं 05.30 बजे तक आवेदन आमंत्रित किया गया है।अभ्यर्थी निर्धारित समय तक आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर-चांपा (छ.ग.) पिन 495668 के नाम से पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं।आवेदन केवल डाक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत दिशा-निर्देश जिले की वेबसाइट httpsÑ//janjgir-champa.gov.in तथा जिला पंचायत जांजगीर-चांपा के सूचना पटल से प्राप्त किए जा सकते हैं।

सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ अग्रसर

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाः इस वर्ष 17,881 किसान लाभान्वित

शाकम्भरी योजना अंतर्गत किसानों को अधिकतम 75 प्रतिशत अनुदान 3234 किसानों मिला लाभ

रायपुर, संवाददाता

/मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन एवं बीज निगम के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर के प्रयासों से अब प्रदेश सब्जि उत्पादन के क्षेत्र में निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। बता दें कि पहले जहां किसान केवल धान की खेती के भरोसे ही रहता था वहां अब सब्जि उत्पादन की ओर रुचि बढ़ रही है। यह सब संभव हो पा रहा है, राज्य और केंद्र शासन द्वारा अलग अलग योजनाओं के तहत किसानो को उन्नत सब्जि बीज तथा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अन्तर्गत संचालित पारदर्शी चैम्पस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किसान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई ड्रीप एरिगेशन सिस्टम पलब्ध कराने से सब्जी की खेती में बढ़ोत्तरी हो रही हैं वहीं सब्जी उत्पादक किसान आर्थिक रूप से समृद्ध भी हो रहे है। ड्रीप सिस्टम जो ''पर ड्राप मोर क्रॉप'' पर आधारित है अर्थात ड्रीप सिस्टम के माध्यम से पौधे को आवश्यक पानी एवं अन्य वांछित पौष्टिक सामग्री सीधे पौधे पर ही जाता है जिससे पानी एवं अन्य सामग्री की बर्बादी नही होती, साथ-ही-साथ किसानों को श्रमिक लागत कम होने से किसानों की आर्थिक क्षति कम होती है तथा मुनाफा में वृद्धि होती है। उन्होंने बताया कि राज्य बीज निगम द्वारा किसानों को शासकीय अनुदान अधिकतम 55 प्रतिशत पर किसानों को ड्रीप एवं स्प्रिंकलर उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में रबी फसल दलहन/तिलहन जैसे चना फसल किसानों द्वारा स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई का भरपुर लाभ लिया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में कुल 17881 कृषकों को (ड्रीप 3281 एवं स्प्रिंकलर 14600) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनांतर्गत ड्रीप/स्प्रिंकलर सिस्टम अनुदान पर प्रदान कर आर्थिक सशक्तिकरण करने में सहयोग किया गया है जो वित्तीय वर्ष समाप्ति तक निरंतर जारी रहेगा।

चौराभांठा मध्यान्ह भोजन प्रकरण में कड़ी कार्रवाई

प्रधान पाठक निलंबित, स्व-सहायता समूह बदला गया, मध्यान्ह भोजन प्रभारी की असंचयी प्रभाव से दो वेतनवृद्धि रोकी

जांजगीर चांपा / कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन में चौराभांटा शासकीय पूव माध्यमिक विद्यालय में मध्यान्ह भोजन व्यवस्था में लापरवाही प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय चौराभांठा की प्रधान पाठक श्रीमती किरण लता शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

प्रकरण की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि मध्यान्ह भोजन संचालन में निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं किया गया। इसके मद्देनज़र विद्यालय में कार्यरत राहुल महिला स्व-सहायता समूह को कार्य से पृथक करते हुए उसके स्थान पर दूसरे पात्र महिला स्व-सहायता समूह को मध्यान्ह भोजन संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही प्रकरण में पर्यवेक्षण स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित मध्यान्ह भोजन प्रभारी श्री जगेश्वर सिंह शिक्षक एल बी शास पूर्व माध्यमिक शाला चौराभांठा की असंचयी प्रभाव से दो वेतनवृद्धि रोकने के आदेश संयुक्त संचालक शिक्षा द्वारा जारी किए गए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी विद्यालयों में सतत निरीक्षण और निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।

अवैध रेत उत्खनन, परिवहन व भंडारण पर की जा रही लगातार कार्रवाई, 01 चैन माउण्टेन व 08 ट्रैक्टर जब्त

जांजगीर-चांपा /

कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन में खनिज विभाग उडनदस्ता दल एवं राजस्व अमला द्वारा जिले के विभिन्न स्थानो पर अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण करने वाले वाहनो, स्थानो का औचक निरीक्षण कर लगातार कार्रवाई की जा रही है।

खनि अधिकारी श्री अनिल कुमार साहू ने बताया कि जांच के दौरान चांपा क्षेत्र से खनिज रेत के अवैध भण्डारण स्थल से 01 ट्रैक्टर (लोडर) एवं अवैध परिवहन कार्य में संलिप्त 04 ट्रेक्टर पाया गया। अवैध भण्डारण व परिवहन कार्य में संलिप्त पाये जाने के कारण उक्त वाहनो को खनिज नियमो के तहत जब्त कर चॉपा थाना के सुरक्षार्थ रखा गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम बरसपुर स्थित हसदेव नदी से खनिज रेत के अवैध उत्खनन कार्य में संलिप्त चैन माउण्टेन मशीन को जब्त कर सील किया गया है। इसी प्रकार तहसील बलौदा क्षेत्र अंतर्गत अवैध रेत परिवहन पर 03 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है।

कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर प्रभावी नियंतत्रण हेतु जिला स्तरीय उडनदस्ता दल एवं राजस्व अमला द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। खनिजो के अवैध उत्खनन, परिवहन,भण्डारण करने वालो के विरूद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 (ख) के तहत कार्यवाही की जा रही है।

बम्हनीडीह क्षेत्र में रेत के 02 अस्थाई भंडारण अनुज्ञप्ति निरस्त

उल्लेखनीय है की विगत दिवस जिले के बम्हनीडीह क्षेत्रांतर्गत छ.ग. (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 के तहत ग्राम अमोदी में मेसर्स आर बी कंस्ट्रक्शन के पक्ष स्वीकृत गौण खनिज रेत के अस्थाई भण्डारण अनुज्ञप्ति क्षेत्र में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियमो का बार-बार उल्लंघन तथा पाई गई अनियमितता का समाधान नहीं किये जाने एवं ग्राम बम्हनीडीह में मेसर्स बाबा सिद्धेश्वर कंस्ट्रक्शन के पक्ष में स्वीकृत खनिज रेत के अस्थायी भण्डारण अनुज्ञप्ति क्षेत्र में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनियमितता किया जाना/भण्डारण नियमो का उल्लंघन तथा कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने कारण उक्त स्वीकृत दोनो अस्थायी भण्डारण अनुज्ञप्ति को निरस्त किया गया है।

खास खबर

पाली में संपन्न हुई सरपंचों की एक अहम बैठक

कोरबा, कोरबा जिले के शिव नगरी पाली स्थित विश्राम गृह में जिला सरपंच संघ का विधिवत गठन किया गया। इस अहम बैठक में जिले के पाँचों विकासखंडों के सरपंच संघ अध्यक्षों सहित बड़ी संख्या में सरपंच साथी मौजूद रहे। सर्वसम्मति से पाली विकासखंड अंतर्गत ग्राम मांगामार के सरपंच छत्रपाल सिंह राज को जिला सरपंच संघ का अध्यक्ष चुना गया। बैठक में संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न पदों पर नियुक्तियाँ की गईं। विजय कुमार मझवार (कोरबा विकासखंड) को सचिव, प्रताप मरावी (पोड़ी-उपरोड़ा) को कोषाध्यक्ष तथा स्नेह लता एवं श्रवण कुमार तंवर को सह-सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं रजनीश मरावी (पाली विकासखंड) को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया।संघ के संरक्षक पद पर दिलाराम नेताम (पाली) और चंद्रिका देवी पोर्ते (पोड़ी उपरोड़ा) को मनोनीत किया गया। इसके अलावा मनोज बाई कंवर (पोड़ी-उपरोड़ा) को महामंत्री तथा मुकेश कुमार राठिया (करतला) को संगठन में महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया।बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिले के प्रत्येक विकासखंड से छह-छह सदस्यों को कार्यकारिणी में शामिल किया जाएगा।

धान बेचने किसान को अपना खसरा पोर्टल में जुड़वाना होगा

कोरबा। जिले के खरीदी केन्द्रों में धान बेचने पंजीयन कराने वाले सभी किसानों को सूचना जारी की गई है कि जिनके खसरे किसान पोर्टल में दर्ज हैं और एग्रीस्टेक पोर्टल में अपडेट फार्मर रिक्वेस्ट लंबित है, वे सभी खसरों को एग्रीस्टेक पोर्टल में जुड़वा लें।

धान उपार्जन की प्रक्रिया में शामिल किसान एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत हों और एग्रीस्टेक पोर्टल में 11 अंकों का फार्मर आईडी बनाकर सभी खसरों का अंकन पूरा करें। 5 दिसंबर तक की स्थिति में आवेदन लंबित है, वे किसान खसरों को एग्रीस्टेक पोर्टल में खुद जोड़ें या संबंधित समिति के एग्रीस्टेक लॉगिन या लोक सेवा केंद्र से इसे कराएं। खसरा जोडने के लिए ऋण पुस्तिका या बी-1, आधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर जरूरी है। किसानों तक जानकारी पहुंचाने कोटवारों से मुनादी, ग्राम पंचायत और समितियों में लंबित किसानों की सूची चस्पा करने और कृषक मित्रों को घर-घर सूचना देने कहा गया है। किसानों की सुविधा के लिए 20 दिसंबर तक जिले में विशेष शिविर लगेंगे।

इसमें समिति प्रबंधक, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और लोक सेवा केंद्रों के वीएलई टीम खसरे एग्रीस्टेक पोर्टल में जोडने की कार्रवाई करेगी। एग्रीस्टेक पोर्टल में फार्मर आईडी नहीं बनाने वाले किसानों को यह आईडी बनवाकर 15 दिसंबर तक एकीकृत किसान पोर्टल में कैरी फॉरवर्ड कराने कहा गया है।

टीपी नगर में कॉपर पाइप चोरी का आतंक, केनरा बैंक फिर बना निशाना

कोरबा, ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में इन दिनों कॉपर पाइप चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे क्षेत्र के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सोमवार को बैंक खुलने के समय ट्रांसपोर्ट नगर स्थित केनरा बैंक में उस वक्त हड़कंप मच गया।

अदाणी फाउंडेशन की पहल : पाँच ग्राम पंचायतों में आंगनवाड़ी केंद्रों को मिली आवश्यक सामग्री

बारपाली तहसील के आठ गांवों के 18 आंगनवाड़ी केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

कोरबा संवाददाता।, जिले के बारपाली तहसील अंतर्गत कोरबा पावर लिमिटेड (केपीएल), पताड़ी ने अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इस पहल के तहत अदाणी फाउंडेशन के माध्यम से आसपास की पाँच ग्राम पंचायतों के आठ गांवों में स्थित कुल 18 आंगनवाड़ी केंद्रों में रसोई के बर्तन, खेल कूद का सामान, कुर्सीयाँ, टेबल, अलमीरा, गद्दे इत्यादि जैसी आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया गया।

अदाणी फाउंडेशन द्वारा यह सामग्री वितरण एवं केंद्रों का उद्घाटन ग्राम पंचायत पताड़ी, खोदले, पहांदा, धंदानी और सरगबुंदिया में किया गया। कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में अदाणी पॉवर के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों, सहित ग्रामीण महिलाएं एवं स्थानीय नागरिक शामिल हुए। कई केंद्रों में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में विधिवत उद्घाटन संपन्न हुआ। सभी संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने भी कार्यक्रम में भाग लेकर केंद्रों का निरीक्षण किया, जिससे सामुदायिक सहभागिता और अधिक मजबूत हुई। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों में आवश्यक सामग्री की कमी को दूर करना तथा पुराने और अनुपयोगी उपकरणों को बदलना रहा। यह कार्य जिला एवं ब्लॉक महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्रीमती रेनू प्रकाश, कोरबा परियोजना अधिकारी श्रीमती ममता तुल्हे तथा करतला परियोजना अधिकारी श्रीमती कीर्ति जैन का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा। अदाणी फाउंडेशन ने बताया कि इस चरण में बुनियादी जरूरतों की पूर्ति पर विशेष ध्यान दिया गया है और आने वाले समय में आंगनवाड़ी केंद्रों में सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त सुधारात्मक कार्य भी किए जाएंगे। नई सामग्री के वितरण से महिलाओं, बच्चों और ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखने को मिला। लाभार्थियों ने एक साथ इतनी व्यापक सहायता मिलने पर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियोंकृसरपंच, पंच एवं विभागीय अधिकारियोंकृजिनमें श्रीमती कीर्ति जैन (करतला परियोजना अधिकारी) और श्रीमती अनुभूति पांडे (पर्यवेक्षक, उरगा सेक्टर) शामिल रहीं, ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे सामुदायिक कल्याण की दिशा में एक सराहनीय प्रयास बताया।

अदाणी समूह द्वारा अपने सामुदायिक सरोकारों के तहत अदाणी फाउंडेशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के कोरबा, रायपुर, सरगुजा, दुर्ग, बलौदाबाजार-भाटापारा एवं बिलासपुर जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना विकास एवं आजीविका उन्नयन के विविध कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

धान खरीदी अभियान में तकनीकी पेचिदगियों की वजह से घटा रकबा, किसान परेशान ,कलेक्टोरेट घेराव की दी चेतावनी

कोरबा संवाददाता

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों का धान खरीदने का कार्य किया जा रहा है लेकिन इसमें कई तरह की गड़बड़ियां सामने आने से किसान काफी परेशान हो रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी किसानों के खेत का रकबा कम होने को लेकर है। इसे लेकर किसान काफी नाराज चल रहे हैं।

लेमरू उपार्जन केंद्र के अंतर्गत आने वाले सात गांव के किसानों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि इस तरह की लापरवाही से वह अपना पूरा धान बेच नहीं पा रहे हैं। किसानों ने कहा है कि 7 गांव के 340 पंजीकृत किसानों के द्वारा सोमवार को कलेक्टर कार्यालय घेराव की तैयारी की जा रही है। समय रहते अगर उनके रकबा में सुधार नहीं किया जाता है तो वह आंदोलन करने के लिए तत्पर हैं।

पंजीयन सुधार में दिक्कत, घुमाया जा रहा लेमरू उपार्जन केंद्र के किसानों ने बताया कि छूटे हुए खसरों के रकबा को ठीक करने के लिए कार्यवाही का

निर्देश जारी किया गया है लेकिन शिविर में जाने पर अधिकारियों के द्वारा घुमाया जा रहा है। ऐसे में वह आखिर कितनी बार चक्कर काटें। इस तरह की समस्या का शीघ्र निराकरण करने की आवश्यकता है ताकि किसान बिना किसी परेशानी के अपना पूरा धान बेच सकें।

20 दिसम्बर तक अभियान जारी

इधर, कोरबा जिले के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड-कोरबा/करतला/कटघोरा/पाली/पोड़ीउप रोड़ा को कृषि विभाग से पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि धान उपार्जन हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत किसानों का एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट अंतर्गत जारी फार्मर आई.डी. में छुटे हुये खसरों को जोड़ने आवश्यक कार्यवाही 10 से 20 दिसम्बर तक किया जाय। कहा गया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 अंतर्गत धान उपार्जन हेतु किसानों को एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन एवं एग्रीस्टेक पोर्टल में संबंधित किसान का फार्मर आई.डी. बनाया जाकर समस्त खसरों का जोड़ना भी आवश्यक है। दिनांक 05.12.2025 तक की स्थिति में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में पंजीकृत किसानों के 27296 खसरें, जो एग्रीस्टेक में न्थ्त् (न्चकंजम थ्तउमत त्मुनमेज) आवेदन हेतु लंबित प्रदर्शित हो रहे हैं, उक्त संबंध में पूर्व में जारी निर्देश अनुसार कार्यवाही की जाय। एग्रीस्टेक पोर्टल में खसरा जोड़ने की कार्यवाही किसान स्वयं से, समिति के एग्रीस्टेक लॉगिन से अथवा लोक सेवा केन्द्र के लॉगिन से करा सकते हैं। जिस हेतु आवश्यक दस्तावेज ऋण पुस्तिकाध्बी-1, आधार कार्ड एवं आधार से लिंक मोबाईल नंबर है।

बिजली विभाग ने बकायादारों के कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू की

कोरबा जिले में बिजली बिल का बकाया 433 करोड़ रुपए पहुंच गया है। बिजली विभाग ने अब बकायादारों के कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक महीने में 2782 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए हैं। इन पर 12 लाख 30 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया था। इनमें से करीब 1 हजार उपभोक्ताओं ने 2 करोड़ 67 लाख रुपए का भुगतान कर दिया है। वहीं अन्य उपभोक्ताओं के घरों में अमला कनेक्शन काटने की कार्रवाई में जुटा है।

जिले में घरों, प्रतिष्ठानों व सरकारी दफ्तरों में पुराने मीटर को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। जिले में जीनस कंपनी को स्मार्ट मीटर का ठेका मिला है। रिचार्ज प्लान तय नहीं होने के कारण स्मार्ट मीटर लगाने के तुरंत बाद प्रीपेड सिस्टम शुरू नहीं किया गया है। इस सिस्टम से खपत के हिसाब से बिजली उपभोक्ता रिचार्ज कराने पर ही बिजली का उपयोग कर पाएंगे। फिलहाल उपभोक्ताओं को खपत के हिसाब से अगले महीने बिल जारी किए जाते हैं। लंबे समय से कई उपभोक्ता बिजली बिल जमा ही नहीं कर रहे हैं। इन पर बिजली वितरण कंपनी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

माहभर में बिल जमा नहीं करने वाले 2782 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए हैं। उन उपभोक्ताओं के यहां भी विजिलेंस टीम पहुंच रही है, जो बकाया राशि जमा नहीं कर रहे हैं। मैदानी अमले की कमी से मैन्युअल तरीके से डिस्कनेक्शन की कार्रवाई प्रभावित होती है। बकाया जमा नहीं कर रहे उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। कंट्रोल रूम से कनेक्शन काटने की टेस्टिंग हुई है। इसका उपयोग कब से होगा, इस पर कोई गाइडलाइन नहीं आई है। -बीके सरकार, एसई, बिजली वितरण कंपनी, कोरबा सर्किल 3830 सरकारी दफ्तरों में लगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर घरेलू उपभोक्ताओं व सरकारी विभागों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम जारी है।

संचालक मंडल/सामान्य सभा एवं जल विहार बुका में फैमिली पिकनिक कार्यक्रम आयोजित

कोरबा । लायंस क्लब ऑफ कोरबा का संचालक मंडल, सामान्य सभा एवं फैमिली पिकनिक कार्यक्रम जल विहार बुका में 12 दिसम्बर 2025 को जल विहार बुका में बड़े ही उत्साह एवं हर्ष के साथ मनाया गया। मिटिंग में दोनो स्कुलों का वार्षिकोत्सव समारोह के आयोजन पर चर्चा की गई। परमानेंट प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की गई। चटपटे व्यंजन के साथ हौजी गेम का भी आयोजन किया गया। सभी सदस्यों ने बढ़ चढकर कर हिस्सा लिया साथ ही नौका विहार का आनंद लिया गया।

कार्यक्रम में पीएमजेएफ लायन जयप्रकाष अग्रवाल पीएमसीसी, एमजेएफ लायन रोहित राजवाड़े अध्यक्ष लायंस क्लब ऑफ कोरबा, लायन रविषंकर सिंह सचिव, एमजेएफ लायन एस.के. अग्रवाल रीजन चेयरमेन, एमजेएफ लायन राजकुमार अग्रवाल (ष्वेता), लायन राजकुमार अग्रवाल (उत्सव), लायन पदमसिंह चंदेल, लायन संतोष खरे, लायन पुरषोत्तम अग्रवाल, लायन दीपक माखीजा, लायन अरविन्द साहु, लायन मनमोहन यादव, लायन कान्ता अग्रवाल, लायन मीना अग्रवाल, लायन अनिमा प्रसाद, लायन भगवती अग्रवाल, लायन ममता वासन, श्रीमती मीना अग्रवाल, श्रीमती रिया माखीजा एवं अन्य सभी लायन सदस्य की उपस्थिति में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

जंगली सुअर का आतंक, कचरा केंद्र के चौकीदार पर हमला, गंभीर रूप से घायल

कोरबा, संवाददाता।

जिले के कटघोरा वनमंडल अंतर्गत दर्री सर्किल में जंगली सुअर के हमले की एक गंभीर घटना सामने आई है। तहसील कार्यालय के पीछे स्थित मणीकंचन कचरा संग्रहण केंद्र में तैनात 60 वर्षीय चौकीदार लोरिक लाल यादव पर जंगली सुअर ने अचानक हमला कर दिया, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, दर्री के नगोईखार श्यामनगर निवासी लोरिक लाल यादव रविवार रात अपनी ड्यूटी पर थे और सोमवार सुबह करीब सात बजे घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान कुछ बकरियां कचरा संग्रहण केंद्र में घुस गईं। बकरियों को बाहर खदेड़ने के लिए वे हाथ में डंडा लेकर थोड़ी दूर जंगल की ओर चले गए।

बकरियों के झुंड में छिपा था जंगली सुअर बताया जा रहा है कि बकरियों के झुंड में एक जंगली सुअर भी मौजूद था, जिसका अंदाजा चौकीदार को नहीं था। अचानक झुंड से निकलकर सुअर ने उन पर हमला कर दिया और दांतों से गंभीर चोटें पहुंचाईं। जान बचाने के लिए लोरिक लाल यादव ने हिम्मत दिखाते हुए डंडे से खुद का बचाव किया और शोर मचाकर मदद की गुहार लगाई। कुछ देर की मशक्कत के बाद वे सुअर को जंगल की ओर खदेड़ने में सफल रहे, लेकिन तब तक वे लहूलुहान हो चुके थे। हमले में उनके गले, पीठ, हाथ, जांघ और पैरों पर गहरे घाव आए हैं।

अस्पताल में भर्ती, वन विभाग ने दी सहायता – घटना की सूचना मिलने पर मणीकंचन केंद्र के सुपरवाइजर ने परिजनों को जानकारी दी। परिजन मौके पर पहुंचे और घायल चौकीदार को ऑटो रिक्शा से मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोरबा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। कटघोरा डीएफओ कुमार निशांत के निर्देश पर वन विभाग के कर्मचारी भी अस्पताल पहुंचे और पीड़ित को विभाग की ओर से तत्काल सहायता राशि प्रदान की गई। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से जंगली जानवरों की बढ़ती आवाजाही पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।

प्रार्थना सभा को लेकर बवाल : ईसाई समुदाय और हिंदू संगठनों में टकराव, पुलिस जांच में जुटी

कोरबा । छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र में रविवार को उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब एक प्रार्थना सभा को लेकर ईसाई समुदाय और हिंदू संगठनों के बीच विवाद हो गया। मामला थाने तक पहुंच गया, जहां दोनों पक्षों की भीड़ जुटने से माहौल गरमा गया।

जानकारी के अनुसार, कटघोरा थाना क्षेत्र के सुतर्रा गांव में ईसाई समुदाय द्वारा एक खेत में पंडाल लगाकर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा का नेतृत्व पास्टर बजरंग जायसवाल कर रहे थे। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में आयोजित इस सभा को लेकर आरोप लगाया गया कि ग्रामीणों को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। गांव की सरपंच संतोषी बाई को सभा की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने इसकी शिकायत की। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और सभा का विरोध किया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि प्रार्थना सभा के दौरान बीमारी और अन्य तकलीफों को प्रार्थना से ठीक करने के दावे किए जा रहे थे, जिससे ग्रामीणों को गुमराह किया जा रहा था। बजरंग दल के जिला अध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर ने आरोप लगाया कि पास्टर बजरंग जायसवाल के साथ बाहर से भी कुछ लोग आए थे। उन्होंने बताया कि पास्टर विशेष रूप से निःसंतान दंपतियों और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को निशाना बनाते हैं

और प्रार्थना से इलाज का दावा करते हैं। इससे ग्रामीण उनके झांसे में आ जाते हैं। नरेंद्र ठाकुर ने यह भी कहा कि पास्टर जायसवाल पहले भी कटघोरा क्षेत्र में चंगाई सभा आयोजित कर चुके हैं, जिसका विरोध हुआ था। उस मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था और बाद में बिना अनुमति सभा न करने की समझाइश दी गई थी, इसके बावजूद गतिविधियां जारी हैं।

घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला और मामला कटघोरा थाने पहुंच गया। थाने में हिंदू संगठनों ने पास्टर बजरंग जायसवाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बजरंग दल ने चेतावनी दी है कि यदि ऐसी गतिविधियां आगे भी जारी रहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने सरपंच की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

ग्राम चुईया को मिली बड़ी सौगात-वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी, पीडीएस भवन का हुआ भूमिपूजन

। **कोरबा** जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती बिजमोती अभिमन्यु राठिया के सतत प्रयासों से ग्राम पंचायत चुईया के ग्रामीणों को बड़ी राहत और सुविधा मिलने जा रही है। वर्षों से लंबित मांग को पूरा करते हुए गांव में नवीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भवन के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ग्राम पंचायत चुईया में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष श्रीमती बिजमोती अभिमन्यु राठिया के मुख्य आतिथ्य में विधिवत भूमिपूजन कर भवन निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया।

भूमिपूजन अवसर पर अध्यक्ष श्रीमती बिजमोती अभिमन्यु राठिया ने ग्रामीणों के साथ पूजा-अर्चना कर निर्माण कार्य की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पीडीएस भवन के निर्माण से अब ग्रामीणों को राशन वितरण में सुविधा मिलेगी, साथ ही व्यवस्था और पारदर्शिता भी सुदृढ़ होगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि जनपद पंचायत क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम के सर्वांगीण विकास के लिए वे निरंतर प्रयासरत रहेंगी। इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीणों ने पीडीएस भवन की स्वीकृति को लेकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह मांग लंबे समय से की जा रही थी, जो अब जनपद अध्यक्ष के प्रयासों से साकार हुई है। ग्रामीणों ने इस उपलब्धि के लिए अध्यक्ष श्रीमती बिजमोती अभिमन्यु राठिया का आभार जताते हुए इसे ग्राम विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। भूमिपूजन कार्यक्रम में जनपद पंचायत कोरबा अध्यक्ष श्रीमती बिजमोती राठिया, प्रतिनिधि अभिमन्यु राठिया, जनपद उपाध्यक्ष श्रीमती कौशल्या देवी कंवर, प्रतिनिधि विश्वनाथ कंवर, जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक-1 प्रतिनिधि राममुरत कंवर, सरपंच श्रीमती पूजा शिवराज सिंह राठिया, सचिव सुरेश खूटे, उपसरपंच श्रीमती शाजिया इरफान जामीन, ग्राम पंचायत चुईया के पंचगण सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर ग्रामीणों ने जनपद अध्यक्ष का पुष्पगुच्छ, फूलमाला एवं साल भेंट कर आत्मीय स्वागत किया तथा ग्राम के सर्वांगीण विकास में सहयोग का संकल्प लिया।

मुख्यमंत्री से CAIT प्रतिनिधियों की सौजन्य मुलाकात, स्वदेशी संकल्प यात्रा में शामिल होने का दिया आमंत्रण

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज विधानसभा स्थित उनके कार्यालय कक्ष में कन्फेडरेशन ऑफइंडिया ट्रेडर्स (ष्ट्वढ्ढञ्ज) के प्रतिनिधियों ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री साय को कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स एवं स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वावधान में देशभर में संचालित स्वदेशी संकल्प यात्रा के अंतर्गत 20 दिसंबर को दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया। उल्लेखनीय है कि स्वदेशी संकल्प यात्रा दुर्ग शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नगर भ्रमण करेगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सशक्त स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, स्थानीय व्यापार को सशक्त बनाना तथा स्वदेशी उद्यमिता के संदेश को जन-जन तक पहुँचाना है।

लाल किले में गूंजा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़ के गेड़ी नृत्य का अद्भुत प्रदर्शन को यूनेस्को ने सराहा

रायपुर । छत्तीसगढ राज्य के बिलासपुर जिले की सांस्कृतिक संस्था 'लोक श्रृंगार भारती' के गेड़ी लोक नृत्य दल द्वारा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) व संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के आमंत्रण पर नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला प्रांगण में गेड़ी नृत्य की प्रस्तुति दी गई। 7 से 13 दिसम्बर तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समारोह में 180 देशों के प्रतिनिधियों की सहभागिता रहीं। समारोह में बिलासपुर के गेड़ी नर्तक दल ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को काफी सराहा गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस गेडी नर्तक दल को बधाई और शुभकामनाएं दीं है केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रभावित हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का नारा दिया समारोह का ऐतिहासिक क्षण तब आया जब भारत के महापर्व दीपावली को यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इस उपलब्धि में छत्तीसगढ़ के गेड़ी लोक नृत्य दल की प्रस्तुति को विशेष सराहना मिली गेड़ी नृत्य की भावपूर्ण और साहसिक प्रस्तुति से केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रभावित हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। गेड़ी नृत्य दल ने अपने रोमांचक प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को रोमांचित कर दिया मुख्य गायक एवं नृत्य निर्देशक अनिल गढ़ेवाल के कुशल नेतृत्व में गेड़ी नृत्य दल ने अपने सशक्त, ऊर्जावान एवं रोमांचक प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को रोमांचित कर दिया।

पर्यावरण संरक्षण और पशुधन संवर्धन की मिसाल- ग्राम सेमरा बी के श्री कीर्तन निषाद की प्रेरक पहल

रायपुर। पर्यावरण संरक्षण और पशुधन हित (पशु कल्याण) आपस में जुड़े हैं, जहाँ पशुधन से ग्रीनहाउस गैस (मीथेन), भूमि क्षरण और जल प्रदूषण होता है, वहीं सतत पशुधन प्रबंधन (जैसे बेहतर चारा, एंटीबायोटिक का विवेकपूर्ण उपयोग) इन प्रभावों को कम कर सकता है, साथ ही जैव विविधता और प्राकृतिक आवासों की रक्षा भी कर सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण आजीविका और पर्यावरण संतुलन में मदद मिलती है।

वातावरण में धुएं और विषैली गैसों के उत्सर्जन में आई कमी

पर्यावरण संरक्षण, पशुधन हित और सतत कृषि की दिशा में धमतरी जिले के विकासखण्ड कुरूद के ग्राम सेमरा बी के प्रगतिशील पशुपालक एवं कृषक श्री कीर्तन निषाद द्वारा किया गया कार्य एक उल्लेखनीय शासकीय सफलता की कहानी के रूप में उभरकर सामने आया है। उनकी दूरदर्शी सोच और जागरूक प्रयासों से लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में फैले पैरा (फसल अवशेष) को सुरक्षित रूप से उनके भाठा में एकत्रित किया गया, जिससे पराली जलाने की हानिकारक परंपरा पर प्रभावी रोक लगाई जा सकी। पराली जलाने से जहां वायु प्रदूषण, भूमि की उर्वरता में कमी तथा जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहीं श्री कीर्तन निषाद की इस पहल ने इन सभी समस्याओं का व्यवहारिक और टिकाऊ समाधान प्रस्तुत किया है। उनके प्रयासों से वातावरण में धुएं और विषैली गैसों के उत्सर्जन में कमी आई, जिससे क्षेत्र के नागरिकों को स्वच्छ वायु का लाभ मिला। यह पहल शासन द्वारा चलाए जा रहे पर्यावरण संरक्षण अभियानों और जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों के उद्देश्यों के पूर्णतः अनुरूप है।

पशुओं के पोषण स्तर में सुधार

इस नवाचारी प्रयास का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष पशुधन संवर्धन से जुड़ा है। एकत्रित पैरा से क्षेत्र में पशुओं के लिए पर्याप्त सूखे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित हुई, जिससे पशुपालकों को चारे की कमी की समस्या से राहत मिली। इससे न केवल पशुओं के पोषण स्तर में सुधार हुआ, बल्कि दुग्ध उत्पादन और पशुपालन की आय में वृद्धि की संभावनाएं भी सुदृढ़ हुई हैं। यह पहल आत्मनिर्भर पशुपालन और ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम है।

ग्रामीण विकास की दिशा में एक आदर्श मॉडल

कीर्तन निषाद की यह उपलब्धि इस बात का सशक्त उदाहरण है कि शासन की नीतियों, जनजागरूकता और व्यक्तिगत पहल के समन्वय से बड़े सकारात्मक परिवर्तन संभव हैं। उनकी सामाजिक जिम्मेदारी, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और किसानों-पशुपालकों के हित में की गई यह पहल अन्य कृषकों के लिए प्रेरणास्त्रोत बन गई है।

विकसित छत्तीसगढ़ की यात्रा के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण चरणः सीएम विष्णुदेव साय

रायपुर।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य रखा है। उनके अनुरूप हमने भी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का लक्ष्य तय किया है। विकसित छत्तीसगढ़ की यात्रा के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण चरण बनाये हैं। हमने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समय अवधि तय की है। जैसे वर्ष 2030 तक हम निकटवर्ती लक्ष्य हासिल करेंगे। इसी तरह साल 2035 तक मध्यवर्ती और 2047 तक दीर्घकालिक लक्ष्य हासिल करेंगे।

अंजोर विजन में 13 क्षेत्रों को किया गया चिन्हांकित

छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डाक्यूमेंट जनभागीदारी का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसे तैयार करने के लिए हमने किसान, युवा, महिला, उद्यमी, कारोबारी समेत समाज के हर वर्ग से सुझाव मांगे। मुझे स्वयं उनसे प्रत्यक्ष बातचीत करने का मौका मिला। इस अंजोर विजन में हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अधोसंरचना जैसे 13 क्षेत्रों को चिन्हांकित कर इनके विकास के लिए 10 मिशन गठित करने

का निर्णय लिया। हम ग्रामीण विकास के साथ.साथ अर्बन प्लानिंग के बेहतरीन मॉडल खड़े कर रहे हैं। नवा रायपुर भविष्य का सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर है। यह शहर मेडिकलए एजुकेशन, टेक्सटाइल, आईटी और एआई का ग्लोबल हब बनने जा रहा है। हम ग्रामीण विकास के साथ.साथ अर्बन प्लानिंग के बेहतरीन मॉडल खड़े कर रहे हैं। नवा रायपुर भविष्य का सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर है। यह शहर मेडिकल, एजुकेशन, टेक्सटाइल, आईटी और एआई का ग्लोबल हब बनने जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बीते वर्षों में गरीबों, किसानों और वंचित वर्गों के लिए अनेक योजनाएं चलाई गईं और राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयास किए गए। उन्होंने बताया कि सरकार की पहली ही कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 18 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई। महिला सशक्तीकरण के लिए महतारी वंदन योजना एक ऐतिहासिक पहल बनी। लगभग 70 लाख माताओं-बहनों को प्रतिमाह 1000 रुपये की सहायता दी जा रही है। डीबीटी के माध्यम से अब तक 22 किस्तों में 14 हजार 306 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज और वनोपज संग्राहकों के हित में तेंदूपत्ता पारिश्रमिक 4000 से बढ़ाकर 5500 रुपये किया गया है। 13 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। चरणपादुका योजना पुनः प्रारंभ की गई है तथा 73 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है।

इको-टूरिज्म, बस्तर पंडुम तथा बस्तर ओलंपिक से बनी बस्तर की पहचान

बस्तर में बस्तर ओलंपिक एवं बस्तर पांडुम जैसे कार्यकमों के माध्यम से बस्तर की आम जनता तक पहुंच रहे है।इस साल बस्तर पांडुम में इस बार 3 गुना लोगों के हिस्सा लेने का अनुमान है। जो हमारी सरकार की सफलता को दिखाती है। आइए इस ऐतिहासिक दिन में हम सभी संकल्प ले की प्रदेश की विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को पूरा करे। इको-टूरिज्म, बस्तर पंडुम तथा बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन नई पहान बना रहे हैं।

8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त

श्री साय ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापार और उद्योग के लिए नई औद्योगिक नीति लागू की गई है। अब तक 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। लॉजिस्टिक पार्क, एयर कार्गो सुविधा और औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए हैं। स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारी सरकार 2 साल में 10 हजार से ज्यादा बेटी बेटा को सरकारी नौकरी दिया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में साढ़े तीन लाख करोड़ का निवेश हुआ है।

आत्मसमर्पण करने वाले और गिरफ्तार हुए माओवादी का पुनर्वास

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदृष्टि एवं केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी के संकल्प के साथ हमारे बहादुर जवानों के अदम्य साहस से माओवाद अब अंतिम पड़ाव पर है। हम मार्च 2026 तक माओवाद की समाप्ति की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले और गिरफ्तार हुए माओवादी का पुनर्वास किया जा रहा है। सुरक्षा के साथ-साथ विकास के जरिए बस्तर को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नियद नेल्ला नार योजना के तहत सुदूर गांवों में राशन, आधार, आयुष्मान कार्ड, आवास, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई गई हैं। बस्तर में स्कूल पुनः शुरू हुए हैं और इको-टूरिज्म, बस्तर पंडुम तथा बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन नई पहचान बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ खनिज और वन संपदा से समृद्ध राज्य मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दो वर्षों में 10 हजार से अधिक बेटियों और बेटों को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।

विवेकानंद पर आधारित लाइट एंड साउंड शो के कलाकार को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान

भिलाई ।

भारत के विभिन्न राज्यों में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन, विचारों और देशभक्ति पर आधारित लाइट एंड साउंड शो को दो भाषाओं में प्रस्तुत करने वाले कलाकार (बेनु नाग, भिलाई) अब तक 70 से अधिक सफल प्रस्तुतियाँ दे चुके हैं।

दिनांक 11 दिसंबर 2025 को माँ शारदा देवी जयंती के पावन अवसर पर, रामकृष्ण मठ, मुनीगुड़ा (ओडिशा) में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित समारोह में उन्हें उनके उत्कृष्ट सांस्कृतिक योगदान हेतु विशेष सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर शो के निर्देशक सुप्रियो सेन और उनके साथी कलाकार सुकृतिका श्रीमति सोनिया नायडू साथ में रहे।

यह सम्मान देशभर में युवा पीढ़ी के बीच स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को जीवंत रूप में पहुँचाने के लगातार प्रयासों की सराहना है।

कार्यक्रम की मुख्य बातें

स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रेरणादायक प्रस्तुति आधुनिक लाइट एवं साउंड तकनीक का प्रभावशाली उपयोग दो भाषाओं में प्रस्तुति से देशभर के दर्शकों से जुड़ाव70+ राष्ट्रीय कार्यक्रमों में निरंतर सहभागिता इस सम्मान के लिए आयोजकों और दर्शकों ने हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

अवैध खनिज परिवहन करते 3 हाईवा और 1 ट्रेलर और नौ ट्रैक्टर जब्त

रायपुर। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में खनिज विभाग की टीम द्वारा अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 हाईवा एवं 1 ट्रेलर वाहन को जब्त किया गया है। खनिज टीम ने टिमरलगा क्षेत्र अंतर्गत गौण खनिज चूना पत्थर के अवैध परिवहन में संलिप्त हाईवा वाहन क्रमांक सीजी 13 एक्यू 6504 को जब्त कर कलेक्टर कार्यालय परिसर, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में अभिरक्षा में रखा गया है। इसी प्रकार दो अन्य हाईवा वाहन क्रमांक सीजी 13 एआर 8389, सीजी 13 एवाई 9848 तथा एक ट्रेलर वाहन क्रमांक सीजी 13 एटी 3111 को जब्त कर थाना सारंगढ़ की अभिरक्षा में सौंपा गया है। उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के अंतर्गत की गई है। गौरतलब है कि कलेक्टर के निर्देशानुसार सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम हेतु खनिज अमले द्वारा आकस्मिक निरीक्षण एवं कार्रवाई की जा रही है। अवैध रेत परिवहन के मामले में 9 ट्रैक्टर जब्त

अवैध रेत परिवहन के मामले में 9 ट्रैक्टर जब्त

रायपुर। रायगढ जिले में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे 9 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। साथ ही संबंधित वाहन मालिकों के विरुद्ध खनिज अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि खनिज निरीक्षक श्री सोमेश्वर सिन्हा एवं जांच दल द्वारा सतत निगरानी के दौरान यह कार्रवाई की गई। जांच में पाया गया कि सभी वाहन बिना किसी वैध अनुमति के रेत का परिवहन कर रहे थे। मौके पर विधिवत जांच के पश्चात वाहनों को जब्त करते हुए वाहन मालिकों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है।

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से लाभान्वित करने के लिए सूर्यसभा का आयोजन

10 ग्रामीणों ने पंजीयन कराया। इसमें 8 ग्रामीणों ने वेंडर का चयन किया।

राजनांदगांव । प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए जिले में जनमानस को निरंतर जागरूक किया जा रहा है। अक्षय ऊर्जा के स्त्रोत अंतर्गत सोलर प्लांट लगाकर बिजली बिल से मुक्ति के लिए जनसामान्य को प्रेरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से अधिक से अधिक नागरिकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों में सूर्यसभा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जनपद पंचायत राजनांदगांव अंतर्गत आने वाले ग्राम भेड़ीकला, टेड़ेसरा, सोमनी, तिलई, पदुमतरा, धर्मापुर, महरूमखुर्द, जोरातराई, सुकुलदैहान, भर्रेगांव में सूर्यसभा का आयोजन किया गया। सूर्यसभा में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई और नागरिकों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान 44 ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीयन कराया। जिसमें 23 ग्रामीणों ने वेंडर का चयन किया। ग्राम पंचायत भेड़ीकला में 10 ग्रामीणों ने पंजीयन कराया। इसमें 8 ग्रामीणों ने वेंडर का चयन किया।

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 पर विस्तृत चर्चा

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने राज्य के दीर्घकालिक विकास विज़न का रखा स्पष्ट रोडमैप

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्य के दीर्घकालिक विकास दस्तावेजछत्तीसगढ़ अंजोर 2047 पर व्यापक और सारगर्भित चर्चा हुई। सदन में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने इस महत्वाकांक्षी विज़न डॉक्यूमेंट पर विस्तृत चर्चा करते हुए इसके उद्देश्य, आवश्यकता और क्रियान्वयन की रूपरेखा को विस्तार से रखा।

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 केवल एक नीति दस्तावेज नहीं, बल्कि अगले 25 वर्षों में राज्य को समृद्ध, आत्मनिर्भर और समावेशी विकास की दिशा में ले जाने का संकल्प है। उन्होंने बताया कि यह विज़न भारत की आज़ादी के 100

वर्ष पूर्ण होने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विशेषताओं को केंद्र में रखा गया है।

वित्त मंत्री चौधरी ने चर्चा में स्पष्ट किया कि तेज़ी से बदलते वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य में राज्य को दीर्घकालिक दृष्टि के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन, तकनीकी विकास और युवाओं की बढ़ती आकांक्षाओं को देखते हुए योजनाबद्ध और दूरदर्शी नीति अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 का उद्देश्य आर्थिक विकास को गति देना, युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करना, किसानों, श्रमिकों और आदिवासी समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना, पर्यावरण संरक्षण के साथ औद्योगिक विस्तार करना, सुशासन, पारदर्शिता और डिजिटल गवर्नेंस को सुदृढ़ बनाना है।

विकास के प्रमुख स्तंभ

वित्त मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 को कई प्रमुख स्तंभों पर आधारित किया गया है। इनमें कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण, औद्योगिक निवेश और स्टार्टअप को बढ़ावा, शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना का विकास और हरित विकास शामिल हैं।उन्होंने विशेष रूप से कहा कि राज्य की युवा आबादी को डेमोग्राफिक डिविडेंड में बदलना इस विज़न का प्रमुख लक्ष्य है। इसके लिए शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और नवाचार को प्राथमिकता दी गई है।सार्वजनिक सहभागिता और पारदर्शितामंत्री चौधरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 को तैयार करने में विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के सुझावों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया में जनभागीदारी और नियमित समीक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी।

बिलाईगढ़ जिले के पूर्व एसपी आशुतोष सिंह सीबीआई में और पुष्कर शर्मा आईबी में देंगे सेवा

सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के पूर्व एसपी अब केंद्र सरकार के आईबी और सीबीआई में सेवा देंगे। यहां से आईपीएस आशुतोष सिंह को महासमुंद जिले में एसपी के पद पर पदस्थ किए गए थे, वहीँ आईपीएस अधिकारी पुष्कर शर्मा माना बटालियन रायपुर में कमांडेंट के पद पर तैनात किए गए थे।

छत्तीसगढ़ कैडर के 2012 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) आशुतोष सिंह को डेपुटेशन पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनविगेस्टकेशन (सीबीआई) पुलिस अधीक्षक (एसपी) बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स के अवर सचिव संजीव कुमार द्वारा इसका आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, सीबीआई में उनका कार्यकाल ज्वाइन करने के बाद 5 साल या आगामी आदेश (जो भी पहले हो) तक होगा। छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी पुष्कर शर्मा को इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर प्रतिनियुक्ति दी गई है। जिसके बाद सोमवार को राज्य सरकार ने उन्हें औपचारिक रूप से रिलीव कर दिया है। गृह मंत्रालय ने कुछ दिन पहले पोस्टिंग आदेश जारी किया था। जिसमें उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर प्रतिनियुक्ति दी गई थी, अब वे नई जिम्मेदारी संभालने दिल्ली रवाना होंगे।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा अस्मा पब्लिशर्स इण्डिया प्राईवेट लि.,जयस्तंभ चौक, रायपुर से मुद्रित कर तथा 5/756 रामसागरपारा, सिंधी स्कूल के पीछे, स्टेशनरी हाऊस, रायपुर 492001 (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक प्रेमेन्द्र अग्रवाल ।
www.lokshakti.in, lokshaktidaily@gmail.com, twitter.com/lokshaktidaily, facebook.com/lokshaktidaily कार्यकारी संपादक : राजेश अग्रवाल (किसी भी विवाद पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा)